

## मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता: एक अच्छा वर्ष

वर्ष 2022 ने लगभग चार दशकों के बाद, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, उच्च मुद्रास्फीति की वापसी को चिन्हित किया। मुद्रास्फीति ने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को भी नहीं छोड़ा। इन गतिविधियों ने पूरे देश में मौद्रिक सख्ती के एक अभूतपूर्व, समकालिक और तेज चक्र को जन्म दिया। प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरों में तीव्र वृद्धि लागू की है, 1970 के दशक के बाद से फेडरल रिजर्व की दर वृद्धि सबसे तेज है। जबकि फेडरल रिजर्व ने पॉलिसी दरों में 425 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि की है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) और बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने क्रमशः 300 बीपीएस और 250 बीपीएस दर वृद्धि लागू की है। आरबीआई ने अप्रैल 2022 में अपने मौद्रिक सख्त चक्र की शुरुआत की और तब से 225 बीपीएस की पॉलिसी रेपो दर वृद्धि लागू की है। परिणामस्वरूप घरेलू वित्तीय स्थितियां सख्त होने लगीं, जो मौद्रिक समुच्चय की कम वृद्धि में परिलक्षित हुईं।

वित्त वर्ष 23 में आरबीआई के पॉलिसी रुख में बदलाव से महामारी के वर्षों के दौरान अधिशेष नकदी की स्थिति में सुधार हुआ। मौद्रिक नीति संचरण अच्छी तरह से चल रहा है क्योंकि नीतिगत दरों में वृद्धि के बाद उधार और जमा दरों में वृद्धि हुई है। सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार में, उच्च मुद्रास्फीति और पॉलिसी दर में वृद्धि की चिंताओं के कारण जून 2022 तक बॉन्ड प्रतिफल ऊपर की ओर था। ये प्रतिफल नवंबर और दिसंबर 2022 में कम हुए, जिसे कच्चे तेल की कम कीमतों, दरों में वृद्धि की धीमी गति, और वैधिक सॉवरेन बॉन्ड प्रकृति में सामान्य नरमी से सहायता मिली।

जबकि वैधिक सख्ती चक्र ने वैधिक दृष्टिकोण को कम करने में योगदान दिया है, ऋण के लिए घरेलू भूख बढ़ रही है। अप्रैल 2022 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा गैर-खाद्य ऋण उठाने दोहरे अंकों में बढ़ रहा है, जिसमें वृद्धि व्यापक-आधारित है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा वितरित ऋण भी बढ़ रहा है। वित्तीय संस्थानों की ऋण देने की क्षमता बढ़ाने में तुलना पत्र क्लीन-अप अभ्यास महत्वपूर्ण रहा है। एससीबी का सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जी एन पी ए) अनुपात 5.0 के सात वर्ष के निचले स्तर तक गिर गया है, जबकि पूंजी-से-जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 16.0 पर स्थिर है और 11.5 की नियामक आवश्यकता से काफी ऊपर है। एनबीएफसी की स्थिति में भी सुधार जारी है। आईबीसी के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वसूली दर अन्य चैनलों की तुलना में वित्त वर्ष 22 में सबसे अधिक थी।

2022 में राजनीतिक और आर्थिक विकास - यूरोप में एक संघर्ष छिड़ना, उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में वृद्धि- का मतलब था कि दुनिया भर के पूंजी बाजारों में वृद्धि की अस्थिरता की विशेषता थी। तथापि, घरेलू पूंजी बाजारों ने कुछ उत्साहजनक रुझान प्रदर्शित किए प्राथमिक इक्विटी बाजारों में सभी खंडों से भागीदारी देखी गई, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के योगदान में वृद्धि हुई, जबकि प्राथमिक निजी ऋण बाजारों में प्लेसमेंट और संसाधन जुटाने में वृद्धि देखी गई। जबकि

निफ्टी 50 और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स के द्वितीयक पूंजी बाजार सूचकांक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह में अस्थिरता के प्रति प्रतिरक्षित नहीं थे, उन्होंने अप्रैल और दिसंबर 2022 के बीच अपने साथियों की तुलना में बेहतर निष्पादन किया। इसके अलावा, दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में निवल एफपीआई प्रवाह सकारात्मक हो गया। इस अवधि के दौरान भारत अस्थिरता सूचकांक (VIX) द्वारा मापी गई अस्थिरता में सूचकांकों ने घटती प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। दोनों विकास भारत के सुदृढ़ वृहद् आर्थिक सिद्धांत और अपेक्षाकृत उछाल वाली मांग के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजार की बढ़ती पहुंच बीमा और पेंशन क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। भारत में बीमा की पैठ लगातार बढ़ रही है, जीवन बीमा की पैठ उभरते बाजारों और वैश्विक औसत से ऊपर है। महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप और एक अनुकूल विनियामक वातावरण ने बीमा बाजार के विकास का समर्थन किया है, जिसमें बढ़ती भागीदारी, उत्पाद नवाचार और जीवन्त वितरण चौनल देख गए हैं। आने वाले दशक में भारत सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), हाल ही में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत के बाद से पेंशन क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति हुई है। इस क्षेत्र में ग्राहकों की संख्या और प्रबंधन के तहत आस्ति (एयूएम) में भारी वृद्धि देखी गई है। सीसीएस (पेंशन) नियमों में छूट, डिजिटलॉकर के साथ इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ई-पीपीओ) का एकीकरण, और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा में छूट जैसे सरकारी उपायों से इस क्षेत्र के विस्तार में मदद मिली है।

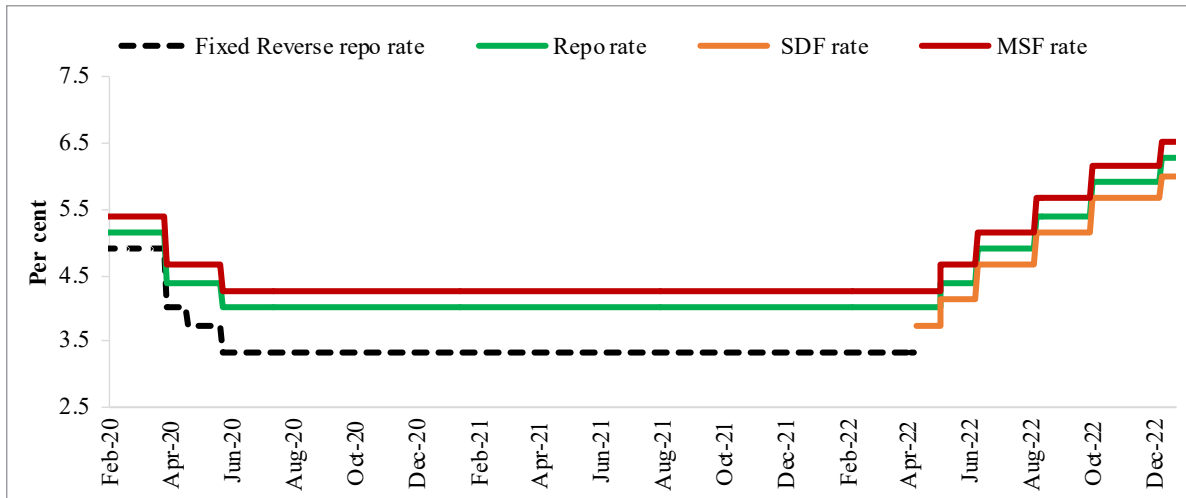
जैसा कि वाधिक केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति के प्रति अपनी लड़ाई में अपने आक्रामक रुख और टेलीग्राफ 'उच्च-से-लंबी' पॉलिसी दरों की पुष्टि की है, दुनिया भर में मौद्रिक स्थिति सख्त रहने की संभावना है। घरेलू स्तर पर, तथापि, विकास के लिए आरबीआई का समर्थन वित्तीय बाजारों में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करेगा। ऋण उठान में वृद्धि के बने रहने की उम्मीद है, और निजी कैपेक्स में तेजी के साथ संयुक्त रूप से एक अच्छे निवेश चक्र की शुरुआत होगी। नियामकों द्वारा वित्तीय प्रणाली में जोखिमों की निरंतर निगरानी और उन्हें नियंत्रित करने के उनके प्रयासों से भी क्रेडिट अपचक्र को मदद मिलेगी। एक बार अनिश्चितता का कोहरा हटने के बाद सुदृढ़ वृहद् आर्थिक सिद्धांत भारत में वैश्विक पूंजी प्रवाह की वापसी को रेखांकित करेंगे। अमृत काल के उद्देश्यों को साकार करने में वित्तीय व्यवस्था अहम भूमिका निभाएगी।

## मौद्रिक विकास

4.1 वित्तीय वर्ष 23 में वधिक आर्थिक परिदृश्य पर मुद्रास्फीति के दबाव बना हुए थे। महामारी से वित्त वर्ष 22 में आर्थिक सुधार के साथ मिलकर मूल्य दबावों का निर्माण लंबे समय से क्षणिक के रूप में देख गया था। आपूर्ति श्रृंखला के सामान्य होने पर इसमें कमी आने की उम्मीद थी। फरवरी 2022 में यूरोप में प्रस्फुटित हुए संघर्ष के कारण उक्त अस्थायीता पर बहस समाप्त हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप, कमोडिटी की कीमतें बढ़ गईं और प्रचलित मुद्रास्फीति के दबावों में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई। इस विकास ने वर्तमान तेज और समकालिक मौद्रिक सख्त चक्र को चालू कर दिया है। संदर्भ स्थापित करते हुए, यह अध्याय वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत के मौद्रिक विकास और वित्तीय प्रणाली के निष्पादन की समीक्षा करेगा। इसमें मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और प्रणाली की नकदी पर उनके प्रभाव की समीक्षा करना और बैंकिंग प्रणाली, क्षेत्रीय ऋण विकास और विभिन्न दिवाला ढांचे के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है। इसके अलावा, यह पूंजी बाजार, बीमा और पेंशन क्षेत्र के विकास को देखता है।

4.2 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मार्च 2020 और मई 2020 के बीच 115 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती को लागू करने के बाद मई 2020 और फरवरी 2022 के बीच पॉलिसी रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखी। खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2022 से आरबीआई के सहनशीलता बैंड की ऊपरी सीमा को पार कर गई है। मूल्य स्थिरता के लिए एक गंभीर जोखिम को भांपते हुए, आरबीआई ने मौद्रिक सख्त चक्र शुरू किया। अप्रैल 2022 की अपनी बैठक में समिति ने स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की शुरुआत की, जिसने सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना आरबीआई के साथ बैंकों द्वारा अतिरिक्त निधि जमा करने की अनुमति दी, जिससे संपार्श्विक-मुक्त तरीके से प्रभावी नकदी प्रबंधन की अनुमति मिलती है। यहां, यह उल्लेखनीय है कि जबकि एसडीएफ विंडो ओवरनाइट डिपॉजिट के लिए उपलब्ध है, रिजर्व बैंक उचित मूल्य निर्धारण के साथ, यदि आवश्यक हो, तो विंडो के तहत लंबी अवधि की अधिशेष नकदी को अवशोषित करने के लिए लचीलेपन को बरकरार रखता है। यहां, यह उल्लेखनीय है कि जबकि एसडीएफ विंडो ओवरनाइट डिपॉजिट के लिए उपलब्ध है, रिजर्व बैंक उचित मूल्य निर्धारण के साथ, यदि आवश्यक हो, तो विंडो के तहत लंबी अवधि की अधिशेष नकदी को अवशोषित करने के लिए लचीलेपन को बरकरार रखता है। एसडीएफ, 3.75 प्रतिशत की दर से पेश किया गया, रिवर्स रेपो दर को नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर की नई मंजिल के रूप में बदल दिया। एमपीसी ने इस बैठक में रुख के बदलाव को 'समायोजन' से 'समायोजन' तथा समायोजित की वापसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विकास का समर्थन करते हुए बदलाव का संकेत दिया, जो मौद्रिक सख्त चक्र की शुरुआत का संकेत देता है।

चित्र 1: पॉलिसी दरें



स्रोत: आरबीआईएल

4.3 प्रतिकूल वधिक विकास, जैसे कमोडिटी की कीमतों में सामान्य रूप से सख्त होने और लंबे समय तक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों की बढ़ती संभावना से उत्पन्न होने वाले बड़े जोखिम को देखते हुए, एमपीसी ने मई 2022 में एक ऑफ-साइकिल बैठक बुलाई। सदस्यों ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर, एसडीएफ और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) में 40 बीपीएस की वृद्धि और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 बीपीएस की वृद्धि के लिए मतदान किया। मई 2022 और दिसंबर 2022 के बीच और पाँच से अधिक बैठकें एमपीसी ने पॉलिसी रेपो दर, एसडीएफ, एमएसएफ और बैंक दर में से प्रत्येक में 225 बीपीएस की संचयी वृद्धि लागू की। कठोरता (टाइटनिंग) के चक्र के शुरुआती चरणों में, समिति ने नोट किया कि पण्य मूल्य प्रेरित मुद्रास्फीतिक दबाव, बढ़ी हुई अस्थिरता और उत्पादन में मंदी के शुरुआती संकेत वैश्विक दृष्टिकोण की विशेषता हैं। दिनांक 5-7 दिसंबर, 2022 की अपनी नवीनतम बैठक में, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर में 35 बीपीएस की बढ़ोतरी की और यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन की वापसी पर अपना ध्यान पुनः आकृष्ट किया कि विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

4.4 पिछले वर्ष के 13 प्रतिशत की तुलना में 30 दिसंबर 2022 को आरक्षित निधि (एमओ) में वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित आरक्षित निधि में एक वर्ष पहले 7.8 प्रतिशत की तुलना में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। घटक पक्ष पर परिसंचरण में मुद्रा (करेंसी इन सर्कुलेशन (सीआईसी) में वृद्धि मोटे तौर पर कोविड-19 के बाद देखे गए स्तरों पर स्थिर रही, रूस-यूक्रेन संघर्ष के प्रकोप के तत्काल बाद में मामूली वृद्धि को छोड़कर, जिसे एहतियाती होल्डिंग्स में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब तक, वित्तीय वर्ष 23 के दौरान एम0 में विस्तार मुख्य रूप से सीआरआर में वृद्धि के साथ, आरबीआई के साथ बैंकों की जमा राशियों द्वारा संचालित था।

तालिका 1: मौद्रिक योग में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिश में)

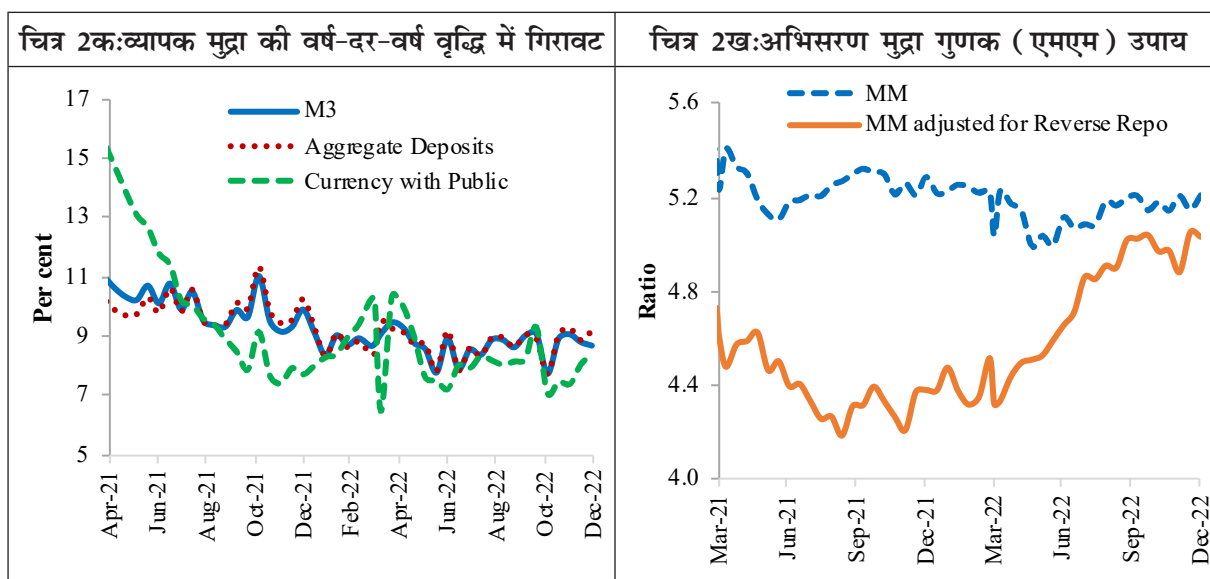
वस्तु	वित्त वर्ष 17^	वित्त वर्ष 18	वित्त वर्ष 19	वित्त वर्ष 20	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23
<b>संचित धन ( एम0 )</b>	<b>-12.9</b>	<b>27.3</b>	<b>14.5</b>	<b>9.4</b>	<b>18.8</b>	<b>13.0</b>	<b>10.3</b>
1. क. प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी)	-19.7	37.0	16.8	14.5	16.6	9.8	8.2
1. ख. भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशि	8.4	3.9	6.4	-9.6	28.5	25.4	17.6
2. नैरो मनी ( एम 1 )	-3.9	21.8	13.6	11.2	16.2	10.7	7.6
3. ब्रॉड मनी ( एम 3 )	6.9	9.2	10.5	8.9	12.2	8.8	8.7
3. क. जनता के पास मुद्रा	-20.8	39.2	16.6	14.5	17.1	10.3	8.4
3. ख. कुल जमा	6.9	5.8	9.6	8.0	11.3	8.4	9.2
मांग जमा	18.4	6.2	9.6	6.8	14.8	10.9	6.2
सावधि जमा	10.2	5.8	9.6	8.1	10.9	8.1	9.1

स्रोत: आरबीआई।

नोट: 31 मार्च, 2017 1 अप्रैल, 2016 से अधिक, एम0, सीआईसी और आरबीआई के पास बैंकर्स डिपॉजिट को छोड़कर।

नोट: 30 दिसंबर, 2023 के अनुसार वित्त वर्ष 23 के आँकड़े।

मौद्रिक घटनाक्रम सख्त वित्तीय स्थितियों को दर्शाते हैं



स्रोत: आरबीआईएल

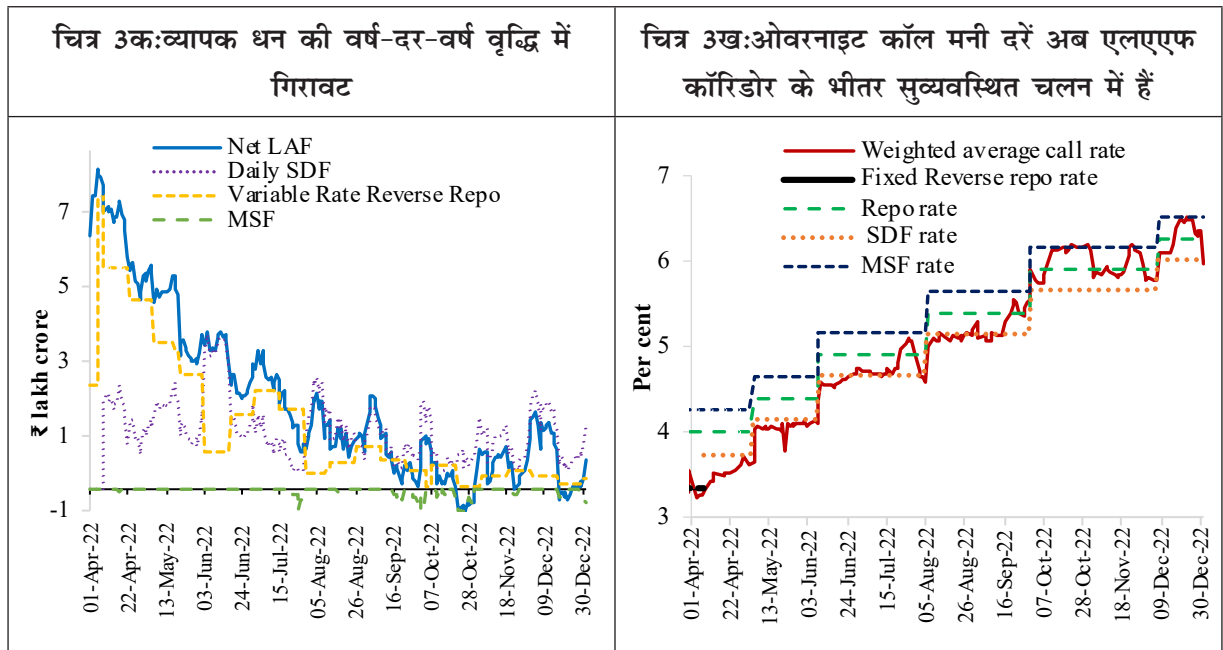
4.5 दिनांक 30 दिसंबर 2022 तक, ब्रॉड मनी स्टॉक (एम3) में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। घटक पक्ष से, कुल जमा सबसे बड़ा घटक रहा है और वर्ष के दौरान अब तक एम3 के विस्तार में सबसे अधिक योगदान दिया है। स्रोतों के बीच, वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक ऋण ने व्यापक धन का विस्तार किया, और सरकार को निवल बैंक ऋण ने इस विस्तार को पूरक बनाया। एम3 में वाणिज्यिक क्षेत्र में बैंक ऋण की हिस्सेदारी में 30 दिसंबर 2022 को 64.3 प्रतिशत की वृद्धि महत्वपूर्ण है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 61.1 प्रतिशत थी, जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण वितरण में वृद्धि को दर्शाती है।

4.6 धन गुणक - एम3 और एम0 का अनुपात - पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5.2 की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2022 की अवधि में मोटे तौर पर 5.1 के औसत पर स्थिर रहा है। तथापि, रिवर्स रेपो के लिए समायोजित एम0, जो विश्लेषणात्मक रूप से आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशि के समान है, अप्रैल 2022 तक बहुत अधिक था। इसलिए, वित्त वर्ष 23 की शुरुआत में समायोजित धन गुणक 4.3 पर कम था। रिवर्स रेपो के लिए समायोजित एम0 अब एम0 के बहुत करीब है; इसलिए, 30 दिसंबर 2022 को मनी मल्टीप्लायर और एडजस्टेड मनी मल्टीप्लायर क्रमशः 5.21 और 5.03 थे।

## नकदी की स्थिति

4.7 रिजर्व बैंक के पारंपरिक और अपरंपरागत मौद्रिक उपायों के जवाब में कोविड -19 के बाद प्रचलित अधिशेष नकदी की स्थिति बदली हुई मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप वित्त वर्ष 2023 के दौरान नरम हो गई, जो समायोजन पर केंद्रित थी। पॉलिसी रेपो दर से ऊपर 25 बीपीएस पर एमएसएफ दर बनाए रखने के साथ, एलएएफ कॉरिडोर पॉलिसी रेपो दर के आसपास सन्तुलित हो गई - इस प्रकार कॉरिडोर की चौड़ाई 50 बीपीएस पर पहुंच गई, जो कि महामारी से पहले थी। सीआरआर में 50 बीपीएस की बढ़ोतरी के आरबीआई के कदम के परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली से ₹ 87,000 करोड़ की प्राथमिक नकदी की निकासी हुई।

## चलनिधि स्थितियों में सुधार



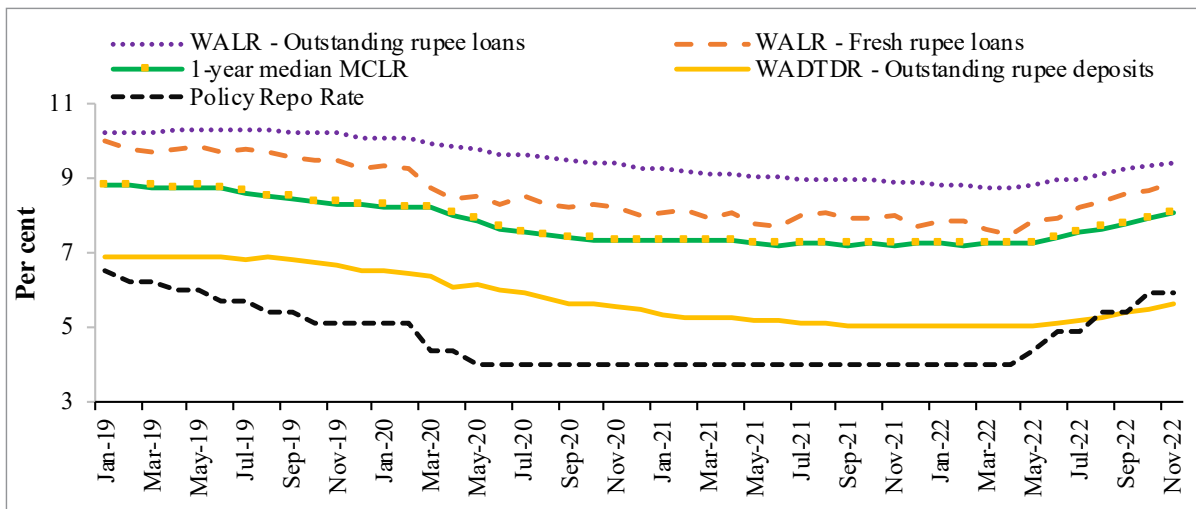
स्रोत: आरबीआई

4.8 वित्त वर्ष 23 (21 दिसंबर 2022 तक) के दौरान दैनिक निवल नकदी अवशोषण औसतन ₹2.5 लाख करोड़ था, जबकि वित्त वर्ष 22 में ₹6.7 लाख करोड़ था। रिजर्व बैंक दो तरफा संचालन करके चलनिधि प्रबंधन में तेज और दक्ष बना रहा। इसने 26 जुलाई और 22 सितंबर 2022 को क्रमशः 3 दिनों में प्रत्येक ₹50,000 करोड़ की दो परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामियों और रातोंरात परिपक्वता के माध्यम से अस्थायी नकदी की तंगी को दूर करने के लिए नकदी डाली। इसने 26 जुलाई और 22 सितंबर 2022 को क्रमशः 3 दिनों में प्रत्येक ₹50,000 करोड़ की दो परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामियों और ओवरनाइट परिपक्वता के माध्यम से क्षणिक नकदी की तंगी को दूर करने के लिए नकदी डाली। अधिशेष नकदी की क्रमिक निकासी ने भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - औसत आधार पर पॉलिसी रेपो दर के करीब कर दिया। डब्ल्यूएसीआर ने एच2 (21 दिसंबर 2022 तक) के दौरान औसतन पॉलिसी रेपो दर से 6 बीपीएस ऊपर कारोबार किया, जबकि एच1 के दौरान यह 28 बीपीएस नीचे था। विभिन्न मुद्रा बाजार दरों पर ब्याज दरें - 91-दिवसीय ट्रेजरी बिल (टी-बिल), 3-महीने के जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र - रेपो दर में वृद्धि के अनुरूप धीरे-धीरे मजबूत हुए।

### मौद्रिक नीति संचरण

4.9 वित्त वर्ष 23 के दौरान बैंकों की उधार और जमा दरों में पॉलिसी रेपो दर में बदलाव के अनुरूप वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 23 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान, बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर और निधि-आधारित उधार दर (एम सीएलआर) की 1-वर्ष की औसत सीमांत लागत में क्रमशः 225 बीपीएस और 115 बीपीएस की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 23 (नवंबर 2022 तक) में नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यू एएलआर) क्रमशः 135 बीपीएस और 71 बीपीएस बढ़ी। जमा पक्ष पर, वित्त वर्ष 23 (अक्टूबर 2022 तक) में बकाया जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में 59 बीपीएस की वृद्धि हुई।

चित्र4: घरेलू ऋण देने और जमा दरों में वृद्धि



स्रोत: आरबीआई

4.10 वित्त वर्ष 23 (नवंबर 2022 तक) के दौरान बैंक समूहों में संचरण का विश्लेषण इंगित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में नए ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर में वृद्धि अधिक थी, जबकि बकाया जमा पर डब्ल्यूएडीटीडीआर और बकाया ऋण पर डब्ल्यूएएलआर निजी बैंकों के लिए अधिक था।

## तालिका 2: सभी बैंक समूहों में ऋण और जमा दरों में अंतरण

बीपीएस में बदलाव	फरवरी 2019 - मार्च 2022			अप्रैल से नवंबर 2022		
	डब्ल्यूएलआर - बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूएलआर - नए रुपए ऋण	डब्ल्यूएडीटीडीआर - बकाया जमा	डब्ल्यूएलआर - बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूएलआर - नए रुपए ऋण	डब्ल्यूएडीटीडीआर - बकाया जमा
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	-153	-252	-169	59	149	51
निजी बैंक	-141	-188	-211	82	101	59
एससीबी#	-150	-232	-188	71	135	59

^: मार्च 31, 2017, अप्रैल 1, 2016 के ऊपर, एम0, सीआईसी और बैंकर जमा आरबीआई के पास को छोड़कर  
\*: वित्तीय वर्ष 23 के आंकड़े दिसंबर 30, 2022 तक के हैं

स्रोत: आरबीआई

नोट : डब्ल्यूएलआर: भारत औसत उधार दर; डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारत औसत घरेलू मीयादी जमा दर।

एमसीएलआर: निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत;

एससीबी में सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंक शामिल हैं।

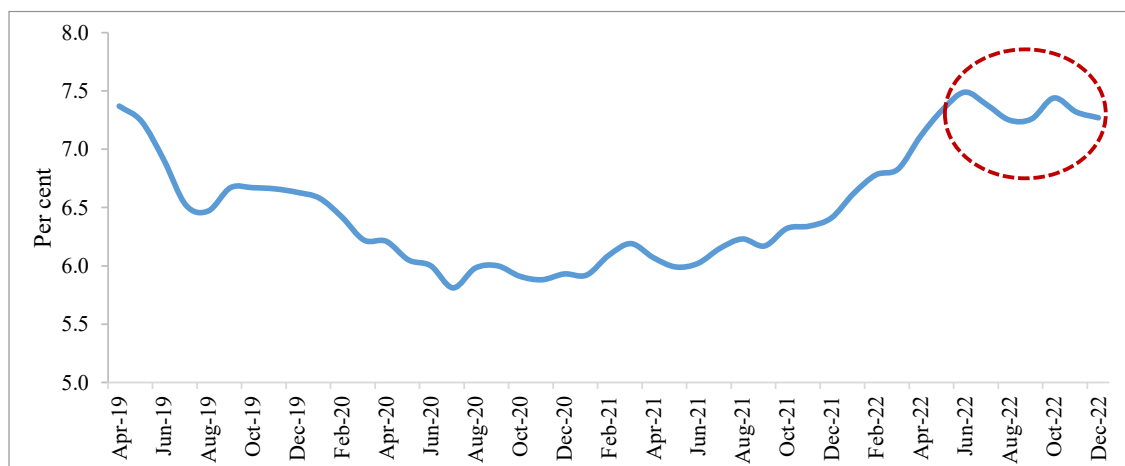
पीएसबी: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

पीविबी: निजी क्षेत्र के बैंक

## जी-सेक बाजार में विकास

4.11 वर्ष 2020 और 2021 तक कमजोर रहने के बाद 2022 में 10 वर्ष के सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल बढ़ा। भारत औसत प्रतिफल वृद्धि कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, प्रमुख केंद्रीय बैंकों के आक्रामक रुख, वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल में मजबूती और रुपये पर दबाव से उपजी घरेलू बॉन्ड बाजार की अस्थिरता को दर्शाती है। जून 2022 में 7.5 प्रतिफल के चरम पर पहुंचने के बाद दिसंबर 2022 में 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर मासिक औसत प्रतिफल 7.3 प्रतिशत रहा। नवंबर और दिसंबर 2022 में प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में वृद्धि की गति में गिरावट और मुद्रास्फीति में कमी के कारण प्रतिफल में कमी आई। प्रतिफल में नरमी के साथ, 2022 की दूसरी छमाही में अस्थिरता में कमी आई है।

चित्र 5: जुलाई से जी-सेक प्रतिफल में कमी आ रही है, तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक बांड प्रतिफल द्वारा समर्थित



स्रोत: एफबीआईएल

4.12 वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान जी-सेक (टी-बिल और एसडीएल सहित) में ट्रेडिंग वॉल्यूम दो साल के उच्च स्तर ₹ 27.7 लाख करोड़ पर पहुंच गया, जिसमें 6.3 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम सरकारी सुरक्षा बाजार में बाजार के खिलाड़ियों/व्यापारियों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

4.13 विदेशी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, प्राथमिक डीलरों और म्यूचुअल फंड के बाद कुल एकमुश्त व्यापारिक गतिविधि में “खरीद” सौदों में 25.0 प्रतिशत और “बिक्री” सौदों में 24.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ निजी क्षेत्र के बैंक समीक्षाधीन तिमाही के दौरान द्वितीयक बाजार में प्रमुख व्यापारिक खंड के रूप में उभरे। निवल आधार पर, विदेशी बैंक और प्राथमिक डीलर निवल विक्रेता थे। इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, निजी क्षेत्र के बैंक और ‘अन्य’ द्वितीयक बाजार में निवल खरीदार थे।

**तालिका 3: जी-सेक में कुल एकमुश्त व्यापार गतिविधि का श्रेणी-वार हिस्सा ( प्रतिशत)\***

श्रेणी	जुलाई - सितंबर 2021		अप्रैल-जून 2022		जुलाई-सितंबर 2022	
	क्रय	विक्रय	क्रय	विक्रय	क्रय	विक्रय
निजी क्षेत्र के बैंक	25.6	28.4	24.3	23.8	25	24.9
विदेशी बैंक	18.6	19.3	20.5	22.7	21.7	22.1
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	16.6	15.6	17.3	16.4	15.7	14
प्राथमिक डीलर	12.3	17.7	13.9	20.3	13.9	19.5
म्यूचुअल फंड्स	14.8	10.1	12.7	8.5	11.2	8.9
अन्य	5.1	3.6	4.1	3.3	5.3	5
सहकारी बैंक	2.9	2.9	3.1	2.8	3.5	3.3
बीमा कंपनियां	3.2	2.1	3.4	2.2	3.1	2.4
वित्तीय संस्थान	1	0.4	0.6	0	0.5	0
कुल	100	100	100	100	100	100

स्रोत: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

नोट: \*: टी-बिल और एसडीएल शामिल हैं।

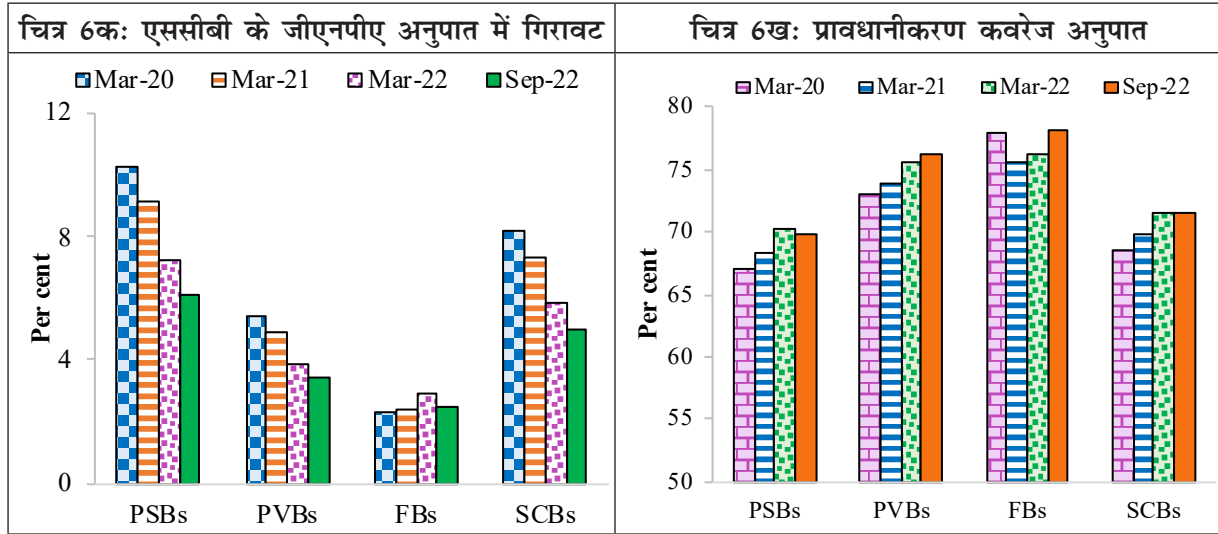
## बैंकिंग क्षेत्र

### लचीली और सुव्यवस्थित पूंजीकृत बैंकिंग प्रणाली

4.14 पिछले दशक के मध्य से आरबीआई और सरकार ने बैंकिंग प्रणाली के तुलन पत्र को साफ और सुदृढ़ करने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करने, मान्यता, संकल्प, पुनर्पूँजीकरण और सुधार के 4आर के दृष्टिकोण को लागू करने जैसे अंशांकित नीतिगत उपायों के संदर्भ में समर्पित प्रयास किए हैं। वर्षों से चल रहे इन निरंतर प्रयासों का परिणाम वर्षों में आस्ति की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में जोखिम अवशोषण क्षमता और एक स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली तुलन पत्र में वृद्धि के रूप में सामने आया है।



### बैंकिंग प्रणाली: संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और तुलन-पत्र को मजबूत करना

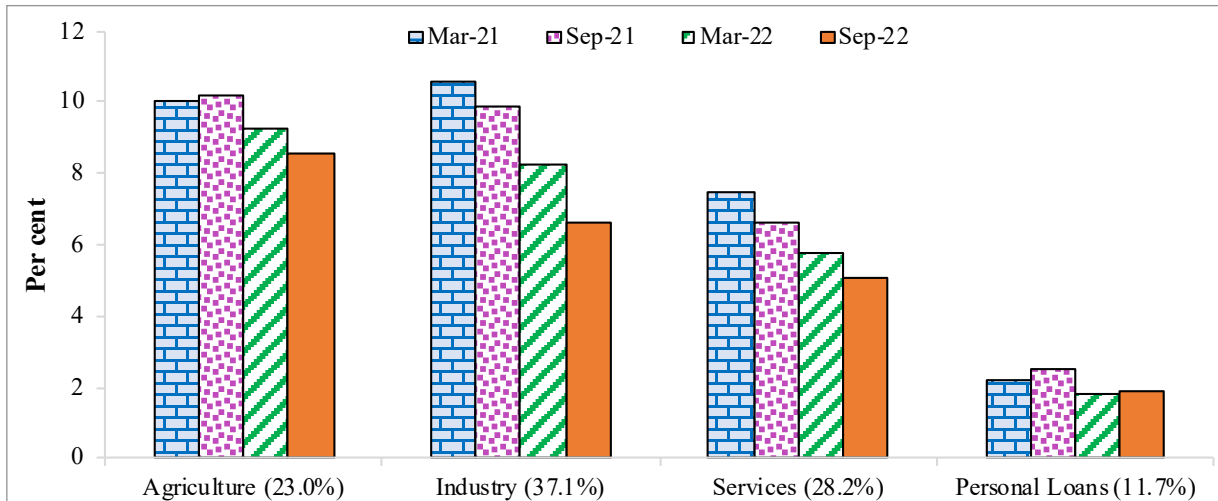


स्रोत: आरबीआई

नोट: एससीबी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए है, पीएसबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए है, पीवीबी निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए है, एफबी विदेशी बैंकों के लिए है।

4.15 परिणामस्वरूप, सभी प्रमुख क्षेत्रों में एससीबी की आस्ति की गुणवत्ता में वर्षों से लगातार सुधार हो रहा है। जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 में 8.2 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2022 में सात वर्ष के निचले स्तर 5.0 प्रतिशत पर आ गया है, जबकि गैर निष्पादित आस्ति (एनएनपीए) कुल आस्तियों के 1.3 फीसदी के दस वर्ष के निचले स्तर पर आ गया है। रिकवरी, अपग्रेड और बट्टे खातों के माध्यम से बकाया जीएनपीए में कम चूक और छूट के कारण यह कमी आई है। हाल के वर्षों में संचित उच्च प्रावधानों के साथ मिलकर, कम जीएनपीए ने एनएनपीए में गिरावट में योगदान दिया। औद्योगिक क्षेत्र में जीएनपीए अनुपात में व्यापक आधार पर सुधार हुआ, तथापि यह रत्न और आभूषण और निर्माण उप-क्षेत्रों के लिए अधिक बना रहा। आगे बढ़ते हुए, आरबीआई के तनाव परीक्षण ढांचे के आधारभूत परिदृश्य के अनुसार, जीएनपीए अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है और मार्च 2023 में इसके 4.9 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान है।

### चित्र 7: जीएनपीए अनुपात में व्यापक आधार पर सुधार

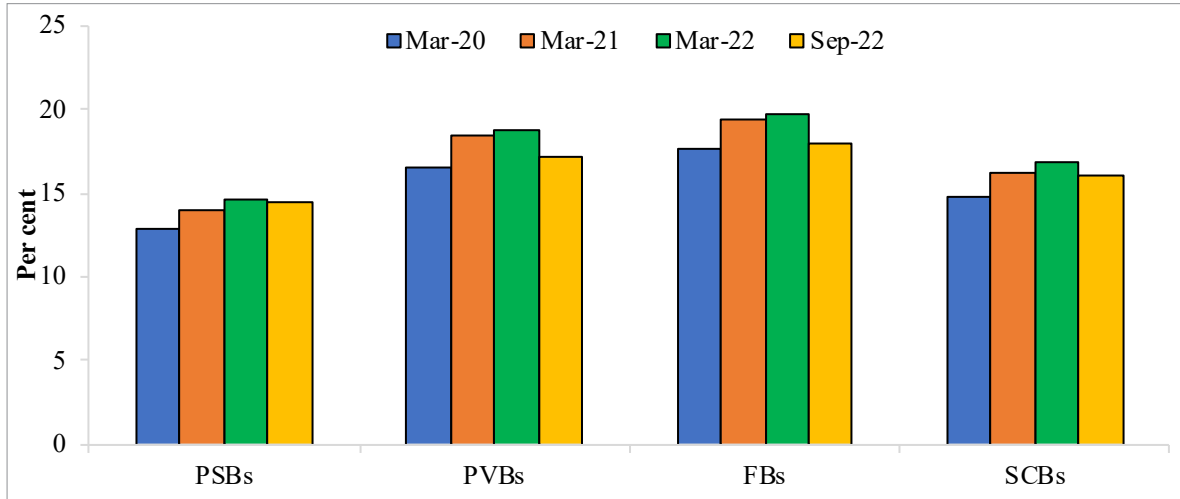


स्रोत: आरबीआई

नोट: लेजेंड के साथ कोष्ठक में संख्या, सितंबर 2022 तक एससीबी के कुल जीएनपीए में संबंधित क्षेत्र के जीएनपीए के हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है।

4.16 इसके अलावा, घटते जीएनपीए के साथ, प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2021 से लगातार बढ़ रहा है और सितंबर 2022 में 71.6 प्रतिशत तक पहुंच गया है। एससीबी का सीआरएआर आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के बाद की अवधि में क्रमिक रूप से बढ़ रहा है। एच 1: वित्त वर्ष 23 के दौरान उधार गतिविधि में तेजी के साथ जोखिम-भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) में वृद्धि के कारण सितंबर 2022 में सीआरएआर में नरमी आई। तथापि, यह 11.5 प्रतिशत की पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) आवश्यकताओं सहित न्यूनतम पूंजी आवयकता से काफी ऊपर है।

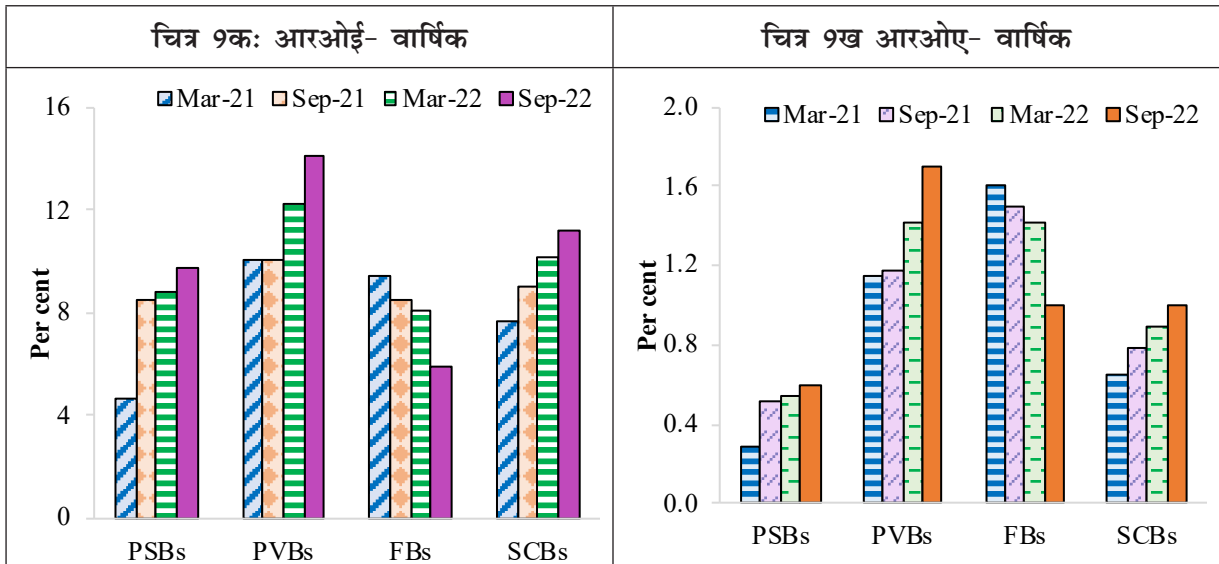
चित्र 8: पूंजी पर्याप्तता अनुपात आवश्यकता मानदंडों से काफी ऊपर है



स्रोत: आरबीआई

4.17 वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही के दौरान एससीबी की लाभप्रदता, जिसे रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) और रिटर्न ऑन एसेट्स (आरओए) के संदर्भ में मापा गया, वित्तीय वर्ष 15 में पिछली बार देखे गए स्तरों में सुधार हुआ। प्रणाली स्तर पर, निवल ब्याज आय (एनआईआई) में मजबूत वृद्धि और प्रावधानों में महत्वपूर्ण कमी के कारण सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में कर के बाद लाभ (पीएटी) में 40.7 प्रतिशत की दो अंकों की वृद्धि देखी गई। क्रेडिट जोखिम के लिए आरबीआई द्वारा किए गए मैक्रो-स्ट्रेस टेस्ट से पता चलता है कि एससीबी सुव्यवस्थित पूंजीकृत हैं और सभी बैंक प्रतिकूल तनाव परिदृश्यों में भी न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का पालन करने में सक्षम होंगे।

निष्पादन संकेतकों में लगातार सुधार

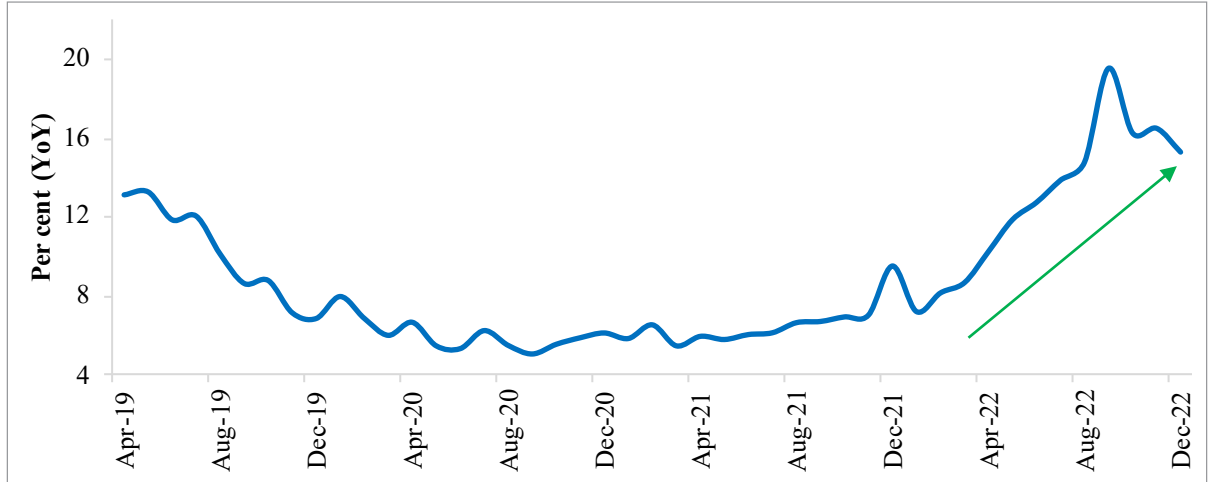


स्रोत: आरबीआई

## सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली और ऋणमुक्त कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा सहायता प्राप्त ऋण वृद्धि

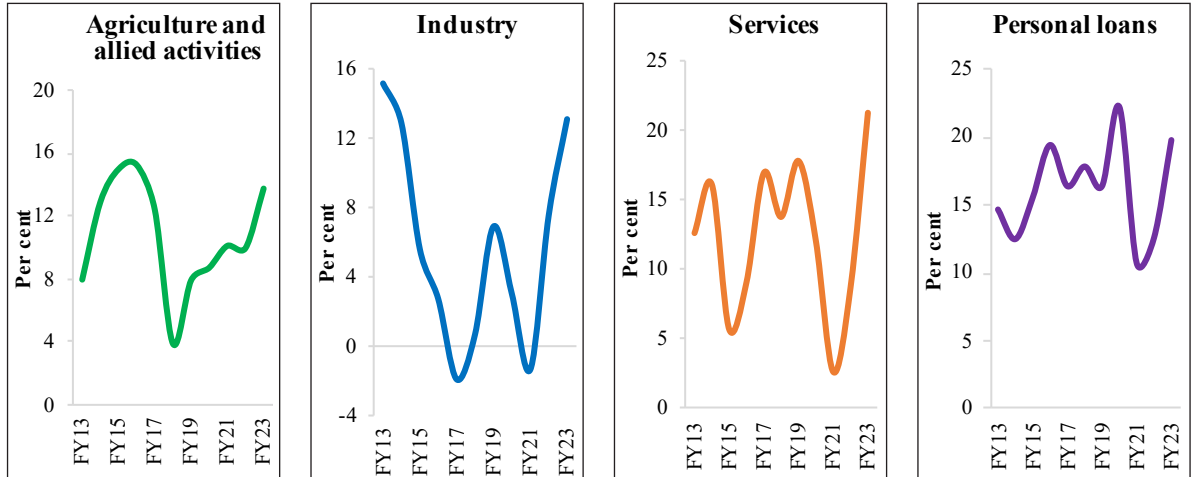
4.18 वित्त वर्ष 22 में आर्थिक गतिविधियों में सुधार, बैंकों और कॉर्पोरेट्स की बढ़ी हुई वित्तीय सुदृढ़ता के साथ, जून 2021 से गैर-खाद्य बैंक ऋण के विस्तार को बल मिला है। गैर-खाद्य बैंक ऋण में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दिसंबर 2022 में बढ़कर 15.3 प्रतिशत हो गई, जो दिसंबर 2011 के बाद सबसे अधिक है। यह न केवल वर्तमान आर्थिक गतिविधियों के विकास में तेजी दिखाता है बल्कि भविष्य में आर्थिक गतिविधियों में निरंतर गति की प्रत्याशा भी दर्शाता है।

चित्र 10: अप्रैल 2022 से गैर-खाद्य बैंक ऋण उच्चतम वृद्धि



स्रोत: आरबीआई

चित्र 11: क्षेत्रीय गैर-खाद्य बैंक ऋण में व्यापक आधारित वृद्धि



स्रोत: आरबीआई

नोट: नवंबर 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 23 के आँकड़े।

4.19 ऋण वृद्धि सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से आधारित रही है, जिसमें मुख्य रूप से गृह ऋण की बढ़ती मांग के कारण खुदरा ऋण में वृद्धि हुई है। आवास की मांग में वृद्धि अधिक निवेश को प्रेरित करती है, जो बदले में विकास और निवेश का एक अच्छा चक्र स्थापित करती है। सरकार के रियायती संस्थागत ऋण और उच्च कृषि ऋण लक्ष्य द्वारा समर्थित कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में तेजी आई। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के प्रभावी कार्यान्वयन से अर्जित लाभों और सरकार की उत्पादन लिंक प्रोत्साहन

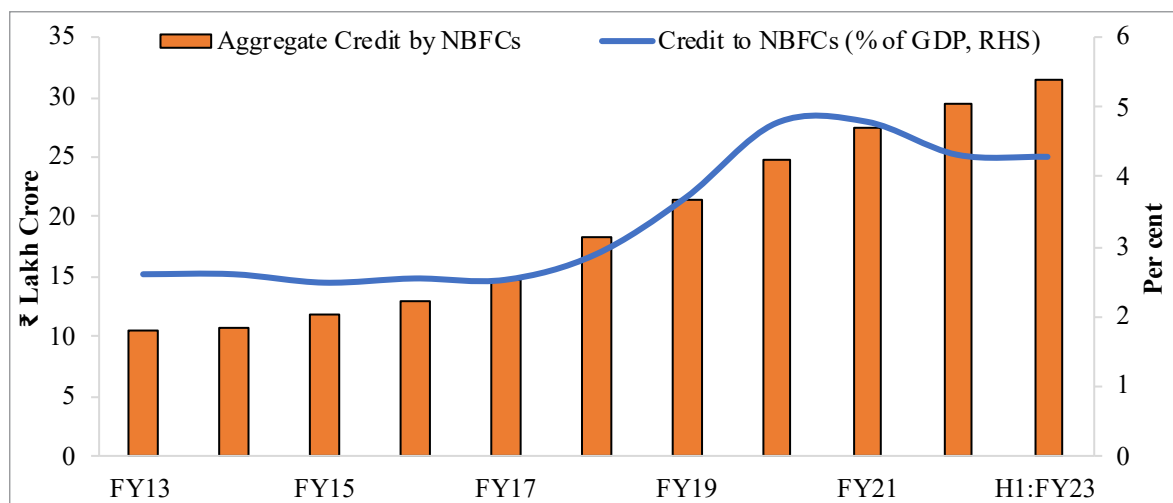
योजना द्वारा प्रदान किए गए सहायता और क्षमता उपयोग में सुधार द्वारा प्रदान किए गए समर्थन द्वारा एमएसएमई को ऋण में तेजी से औद्योगिक ऋण वृद्धि में उछाल आया है। सेवाओं में ऋण वृद्धि एनबीएफसी, वाणिज्यिक अचल संपत्ति और व्यापार क्षेत्रों में ऋण में सुधार से प्रेरित थी।

4.20 विदेशी निर्गमों में कमी और निजी इक्विटी (पीई)/उद्यम पूंजी (वीसी) द्वारा कम निवेश के साथ, कॉर्पोरेट क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को घरेलू संसाधनों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। वित्त वर्ष 23 के दौरान घरेलू इक्विटी बाजारों के प्राथमिक खंड से जुटाई गई धनराशि में गिरावट आई, नियमित परिचालन और क्षमता विस्तार के लिए बैंक ऋण पर निर्भरता बढ़ रही है। साथ ही, वार्षिक (122.0 प्रतिशत, वाई ओवाई) और अर्ध-वार्षिक आधार (172.5 प्रतिशत; सितंबर 2022 मार्च 2022 की तुलना में) दोनों पर वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात तेजी से बढ़ा। पिछले कुछ वर्षों में जमाराशियों के संचयन ने बैंकों को बढ़ती हुई ऋण मांग को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाया है। यहां, कम एनपीए अनुपात और अधिक मजबूत कॉर्पोरेट क्षेत्र के बुनियादी सिद्धांतों के साथ अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंकिंग प्रणाली बढ़ती ब्याज दरों के साथ नहीं, उत्पादक निवेश के अवसरों में बैंक ऋण के प्रवाह को बढ़ाना जारी रखेगी।

### गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ( एनबीएफसी ) का सुधार जारी है

4.21 भारतीय वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी क्षेत्र का बढ़ता महत्व सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के साथ-साथ एससीबी द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में एनबीएफसी के क्रेडिट में लगातार वृद्धि से परिलक्षित होता है। विभिन्न नीतिगत पहलों द्वारा समर्थित, एनबीएफसी महामारी के झटकों को सहन कर सकती हैं। उन्होंने वित्त वर्ष 22 के दौरान तुलन पत्र समेकन, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार, संवर्धित पूंजी बफर और लाभप्रदता द्वारा चिह्नित वित्तीय सुदृढ़ता का निर्माण किया।

चित्र 12: एनबीएफसी को और उनके द्वारा संवितरित ऋण में वृद्धि

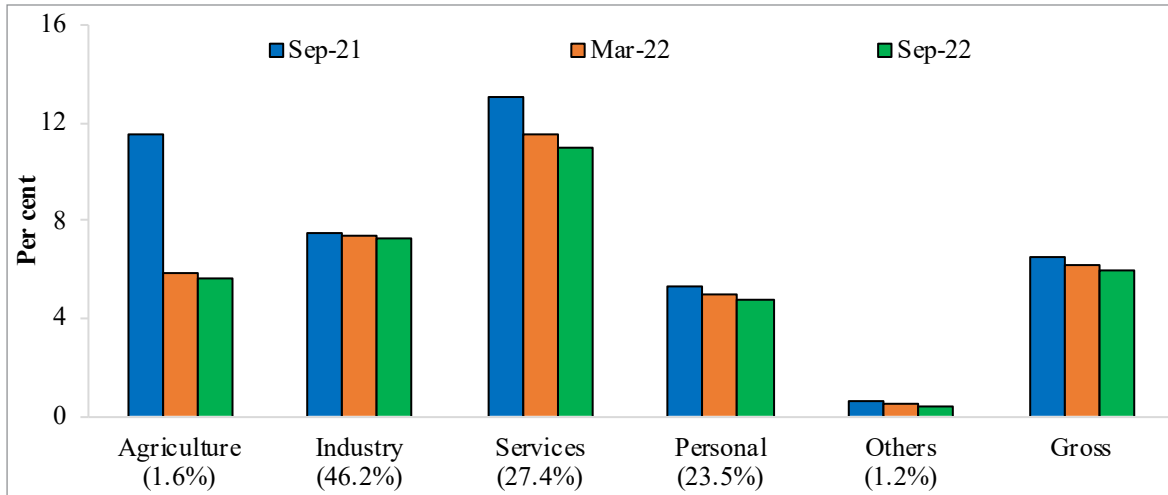


स्रोत: आरबीआई

नोट: वित्त वर्ष 23 (एच1) के लिए एनबीएफसी को क्रेडिट (जीडीपी का प्रतिशत) वित्त वर्ष 23 के लिए एनएसओ के पहले ईई और सितंबर 2022 तक एनबीएफसी द्वारा क्रेडिट के आधार पर अनुमानित है।

4.22 आस्ति की गुणवत्ता में निरंतर सुधार एनबीएफसी के गिरते जीएनपीए अनुपात में महामारी की दूसरी लहर (जून 2021) के दौरान दर्ज किए गए 7.2 प्रतिशत के शिखर से सितंबर 2022 में 5.9 प्रतिशत तक देखा गया है, जो पूर्व महामारी स्तर के करीब पहुंच गया है। यद्यपि यह नरमी सभी क्षेत्रों में देखी गई, सेवा क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात दो अंकों में बना हुआ है।

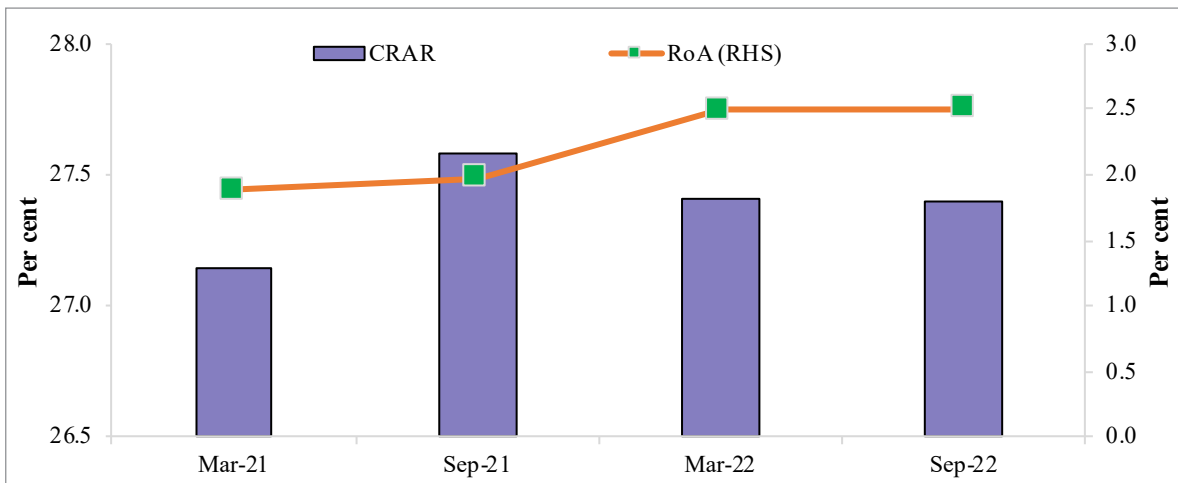
चित्र 13: जीएनपीए अनुपात में गिरावट: सभी क्षेत्रों में एनबीएफसी की आस्ति की गुणवत्ता में सुधार



स्रोत: आरबीआई

नोट: ब्रैकेट में संख्या सितंबर -22 में जीएनपीए में क्षेत्रीय शेयरों का प्रतिनिधित्व करती है।

चित्र 14: एनबीएफसी का प्रदर्शन: मजबूत पूंजी स्थिति के साथ आरओए की भरपाई करना

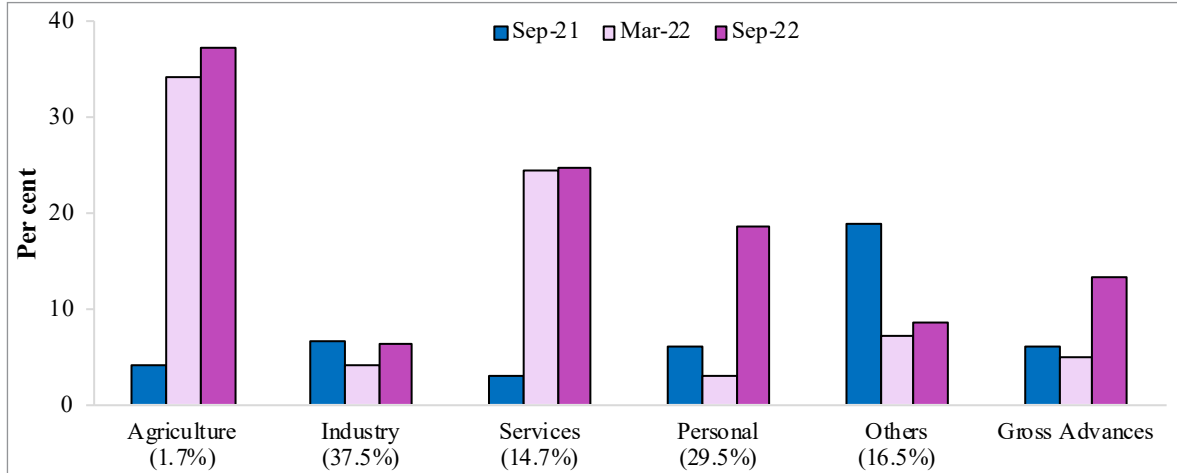


स्रोत: आरबीआई

4.23 जीएनपीए में गिरावट के साथ, एनबीएफसी की पूंजी की स्थिति भी सितंबर 2022 के अंत में 27.4 प्रतिशत के सीआरएआर के साथ मजबूत बनी हुई है, जो मार्च 2022 में 27.6 प्रतिशत से थोड़ा कम है। तथापि, यह नियामक आवश्यकता से काफी ऊपर है। 20 बीपीएस की गिरावट मुख्य रूप से आरडब्ल्यूए में वृद्धि के कारण थी क्योंकि ऋण में तेजी आई थी। लगातार आधे वर्षों में आरओए में सुधार हुआ है। 152 एनबीएफसी के नमूने के लिए एनबीएफसी क्षेत्र के ऋण जोखिम झटकों के लचीलेपन का आकलन करने के लिए आरबीआई के तनाव परीक्षण से पता चलता है कि एनबीएफसी की संख्या जो 15 प्रतिशत की न्यूनतम विनियामक पूंजी आवश्यकता को पूरा करने में विफल होगी, बेसलाइन परिदृश्य के तहत 8 प्रतिशत थी। यह क्रमशः मध्यम और गंभीर तनाव परिदृश्यों के तहत 10 प्रतिशत और 13 प्रतिशत तक बढ़ जाता है।

4.24 सितंबर 2022 तक कुल बकाया राशि ₹ 31.5 लाख करोड़ के साथ, एनबीएफसी द्वारा दिया जाने वाला ऋण गति पकड़ रहा है। एनबीएफसी ने अपनी तुलन पत्र से औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ी मात्रा में ऋण देना जारी रखा, इसके बाद खुदरा, सेवाओं और कृषि का स्थान आता है। सेवा क्षेत्र के लिए ऋण (बकाया ऋण में हिस्सेदारी 14.7 प्रतिशत) और व्यक्तिगत ऋण (29.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी) ने मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की।

चित्र 15: उद्योग में मामूली सुधार के साथ सभी क्षेत्रों में एनबीएफसी द्वारा ऋण संवितरण में मजबूत वृद्धि



स्रोत: आरबीआई

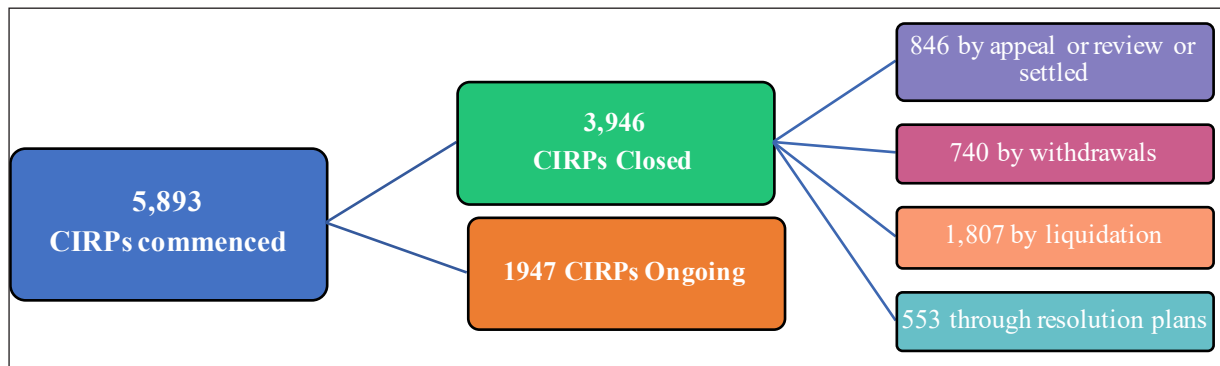
नोट: ब्रैकेट में संख्याएं सितंबर-22 में बकाया ऋणों में क्षेत्रीय श्रेणियों से मेल खाती हैं

### दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत की गई प्रगति

#### व्यापार की सुगमता: 'निकास की प्रक्रिया को सुगम बनाना'

4.25 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) ने संकटग्रस्त फर्मों के बाहर निकलने की सुविधा प्रदान की है, जिससे दुर्लभ आर्थिक संसाधनों को अधिक उत्पादक उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। दिसंबर 2016 में आईबीसी की स्थापना के बाद से, सितंबर 2022 के अंत तक 5,893 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएँ (सीआईआरपी) शुरू हो चुकी थीं, जिनमें से 67 प्रतिशत को बंद कर दिया गया है। इनमें से, लगभग 21 प्रतिशत अपील या समीक्षा या निपटारे पर बंद कर दिए गए थे, 19 प्रतिशत वापस ले लिए गए थे, 46 प्रतिशत परिसमापन के आदेश समाप्त हो गए थे, और 14 प्रतिशत संकल्प योजनाओं के अनुमोदन में समाप्त हो गए थे। कोड एक कॉर्पोरेट देनदार (सीडी) को स्वेच्छा से खुद को परिसमापन करने के लिए प्रदान करता है, जो कोड के तहत निर्धारित कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन है। सितंबर 2022 के अंत तक 1,351 कॉर्पोरेट व्यक्तियों ने कोड के तहत स्वैच्छिक नकदीकरण की शुरुआत की।

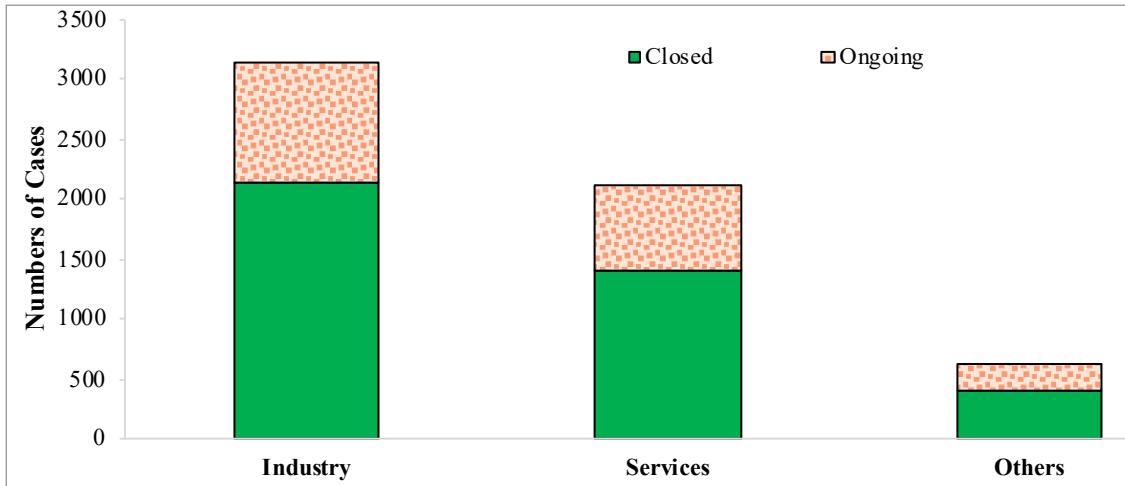
चित्र 16: स्थापना से सीआईआरपी की स्थिति ( सितंबर 2022 तक )



स्रोत: आईबीबीआई (Insolvency and Bankruptcy Board of India)

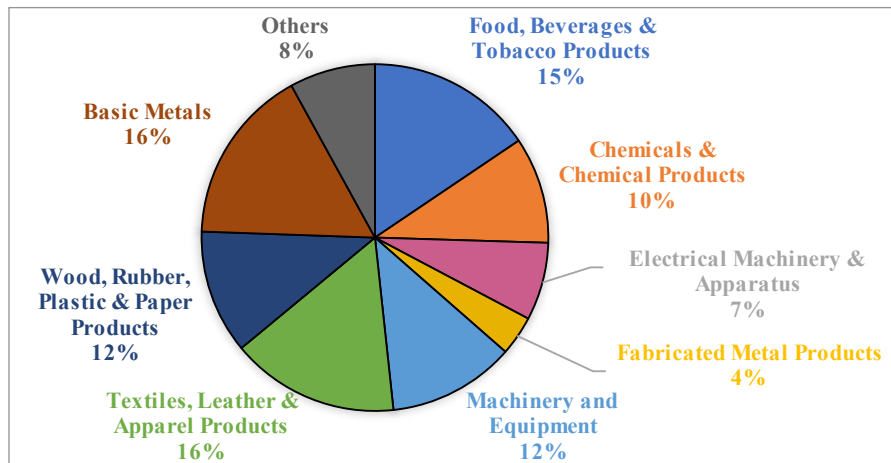
4.26 क्षेत्रीय विश्लेषण से पता चलता है कि चल रहे सीआईआरपी का 52 प्रतिशत उद्योग से संबंधित है, इसके बाद सितंबर 2022 तक सेवा क्षेत्र में 37 प्रतिशत है। इसके अलावा, उद्योग के भीतर, शुरू किए गए सीआईआरपी का 74 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र से था। इनमें से कपड़ा, मूलभूत धातु और खाद्य क्षेत्र चालू सीआईआरपी के 48 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं। जबकि सेवा क्षेत्र में, चल रहे सीआईआरपी का 60 प्रतिशत रियल एस्टेट, किराये और व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित है।

चित्र 17: क्षेत्रवार सीआईआरपी की स्थिति ( सितंबर 2022 तक )



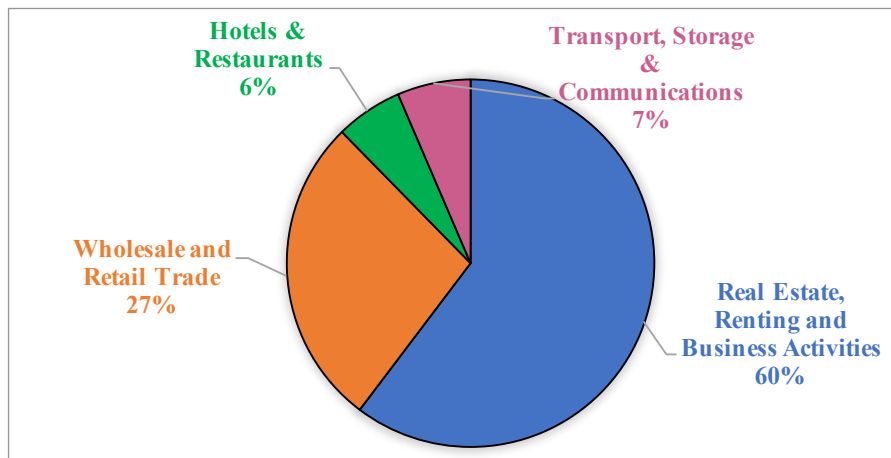
स्रोत: आईबीबीआई

चित्र 18: विनिर्माण क्षेत्र में चल रहे सीआईआरपी का क्षेत्रीय विभाजन



स्रोत: आईबीबीआई

चित्र 19: सेवा क्षेत्र में चल रहे सीआईआरपी का क्षेत्रीय विभाजन



स्रोत: आईबीबीआई

## व्यवहारिक परिवर्तन: व्यापार संबंधों को रिकोड करना

4.27 कोड के दूरगामी स्पिल-ओवर प्रभावों में से एक देनदारों के बीच इसके द्वारा व्यवहारिक परिवर्तन किया गया है। सीआईआरपी के शुरू होने पर सीडी पर नियंत्रण खोने के डर ने हजारों देनदारों को दिवाला कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अपना बकाया चुकाने के लिए मजबूर कर दिया है। 30 सितंबर, 2022 तक, 7.3 लाख करोड़ के अंतर्निहित डिफॉल्ट वाले सीडी के सीआईआरपी शुरू करने के लिए 23,417 आवेदनों को सीआईआरपी में शामिल करने से पहले निपटा दिया गया था।

### संकटग्रस्त आस्तियों का 69 प्रतिशत बचा लिया गया, वसूली मान परिसमापन मूल्य का लगभग 178 प्रतिशत

4.28 30 सितंबर, 2022 तक 553 सीआईआरपी का समाधान हो चुका है। शुरुआत में संकटग्रस्तफर्मों के बहुत कम मूल्य के बावजूद, संहिता द्वारा 69 प्रतिशत संकटग्रस्त आस्तियों को बचाया गया। कुल मिलाकर, सीआईआरपी के आरंभकर्ताओं के लिए मूल्य प्राप्त के संदर्भ में (जिसमें वित्तीय लेनदार, परिचालन लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार शामिल हैं), समाधान योजनाओं से 2.4 लाख करोड़ प्राप्त हुए, जो परिसमापन मूल्य का 177.6 प्रतिशत और बचाए गए 553 सीडी के उचित मूल्य का 84 प्रतिशत है। इसके अलावा, परिसमापन मूल्य की तुलना में संकल्प योजनाओं के तहत वित्तीय लेनदारों द्वारा वसूली 201 प्रतिशत थी, जबकि उनके द्वारा वसूली उनके दावों का 33 प्रतिशत थी।

### परिसमापन प्रक्रिया के तहत वसूल किए गए मूल्य का 92 प्रतिशत

4.29 1807 सीडी सितंबर 2022 तक परिसमापन के आदेशों के साथ समाप्त हो गईं। इन सीडी आस्तियों का मूल्य जमीन पर कुल दावा राशि के 8 प्रतिशत से कम था। हालांकि, परिसमापन में समाप्त होने वाले सीआईआरपी के 76 प्रतिशत से अधिक (1774 में से 1349 जिसके लिए डेटा उपलब्ध हैं) पहले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के पास थे और/या निष्क्रिय हैं। अधिकांश कॉर्पोरेट देनदारों का आर्थिक मूल्य जो परिसमापन में समाप्त हो गया था, सीआईआरपी में भर्ती होने से पहले ही लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 429 सीडी का पूरी तरह से परिसमापन कर दिया गया है। संहिता ने इन कंपनियों के परिसमापन के माध्यम से 92 प्रतिशत मूल्य की वसूली की सुविधा प्रदान की है।

तालिका 4: 30 सितंबर के अनुसार संकटग्रस्त आस्तियों का बचाव (राशि करोड़ रुपये में)

संकटग्रस्त आस्तियों का बचाव	संकल्प द्वारा बचाई गई कंपनियां	कंपनियों को परिसमापन का आदेश दिया	कुल
कंपनियों की संख्या	553	1807	2360
सकल दावे	7,90,626	8,28,180	16,18,806
परिसमापन मूल्य	1,37,119	60,143	1,97,261
कुल दावों के % के रूप में उपलब्ध आस्तियां	17.3	7.3	12.19
संकल्प मूल्य	2,43,452	लागू नहीं	2,43,452
परिसमापन मूल्य के % के रूप में संकल्प मूल्य	177.6	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल दावों के : के रूप में संकल्प मूल्य	30.8	लागू नहीं	लागू नहीं
औसत समय लिया गया	561 दिन	437 days	लागू नहीं
समाधान मूल्य का लागत :	0.6	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोत: आईबीबीआई



## एनपीए: आईबीसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उच्चतम राशि वसूल करता है।

4.30 आरबीआई आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में लोक अदालत, सरफेसी अधिनियम और डीआरटी जैसे अन्य चैनलों की तुलना में आईबीसी के तहत एससीबी द्वारा वसूल की गई कुल राशि सबसे अधिक रही है।

4.31 आईबीसी जैसे सार्वजनिक नीलामी-आधारित समाधान मॉडल में हेयरकट की सीमा उस छूट का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी मांग दबावग्रस्त इकाई को लाभकारी कारबार वाले संस्थान के रूप में प्राप्त करने के लिए बाजार मांग करता है। चूंकि इन आस्तियों में महत्वपूर्ण मूल्य विनाश पहले ही हो सकता है, स्वीकृत दावों के साथ प्राप्त मूल्य की तुलना समाधान प्रक्रिया की प्रभावशीलता का एक उचित संकेतक नहीं हो सकती है। इसके अलावा, रिकवरी की दर कई कारकों पर निर्भर है, जिसमें समग्र वृहद् आर्थिक वातावरण, इकाई और उसके क्षेत्र की कथित विकास संभावनाएं और इकाई के आंतरिक मूल्य में क्षरण की सीमा शामिल है। एक व्यापक आधार वाली रिकवरी के रूप में, इन कारकों के वित्तीय समाधान<sup>3</sup> के लिए अनुकूल होने की संभावना है।

तालिका 5: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विभिन्न माध्यमों से वसूल की गई राशि (राशि करोड़ में)

रिकवरी चैनल	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि*				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22(P)
लोक अदालतें	1,811	2,750	4,211	1,119	2,777
डीआरटी	7,235	10,552	9,986	8,113	12,114
सरफेसी एक्ट	26,380	38,905	34,283	27,686	27,349
आईबीसी	4,926	66,440	1,04,117	27,311	47,421
<b>कुल</b>	<b>40,352</b>	<b>1,18,647</b>	<b>1,52,597</b>	<b>64,229</b>	<b>89,661</b>

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई और आईबीबीआई  
 नोट: पी: अर्न्तम, डीआरटी ऋण वसूली न्यायाधिकरण के लिए है  
 नोट \*: दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि को संदर्भित करता है, जो कि दिए गए वर्ष के दौरान और साथ ही पिछले वर्षों के दौरान संदर्भित मामलों के संदर्भ में हो सकता है।

## पूंजी बाजार में विकास

वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितता, अभूतपूर्व मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति को सख्त करना, अस्थिर बाजार, आदि के परिणामस्वरूप निवेशकों की भावना को ठेस पहुंची है, जिससे वित्त वर्ष 23 में वैश्विक पूंजी बाजारों के निष्पादन में गिरावट आई है। तथापि वैश्विक व्यापक आर्थिक और वित्तीय बाजार के विकास ने भारतीय पूंजी बाजारों पर कुछ प्रभाव डाला, कुल मिलाकर भारत के पूंजी बाजार का वर्ष अच्छा रहा।

## प्राथमिक बाजार

### इक्विटी: सार्वजनिक पेशकश के साथ बड़ी संख्या में एसएमई सामने आ रहे हैं

4.32 अप्रैल से नवंबर 2022 तक, वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल के बावजूद प्राथमिक बाजार का उछाल देखा गया है। वित्त वर्ष 22 की तुलना में, एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने वाली फर्मों की संख्या में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तथापि जुटाई गई राशि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आधी हो गई।

4.33 यद्यपि अभी तक आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाने के मामले में यह वर्ष कमजोर रहा है, सार्वजनिक पेशकश के साथ आने वाले एसएमई की संख्या काफी उत्साहजनक रही है। वित्त वर्ष 22 (नवंबर 2021 तक) की तुलना में, इस वर्ष न केवल आईपीओ के साथ आने वाले एसएमई की संख्या लगभग दोगुनी हुई, बल्कि उनके द्वारा जुटाई गई कुल धनराशि पिछले वर्ष की समान अवधि में उनके द्वारा जुटाई गई राशि से लगभग तीन गुना अधिक थी।

4.34 इसके अलावा, इस वर्ष भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ भी देखा गया। मई 2022 में, केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया और इसे स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कर दिया, जिससे एलआईसी का आईपीओ भारत में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ और 2022 का विश्व स्तर पर छठा सबसे बड़ा आईपीओ बन गया। नवंबर, 2022 तक प्राथमिक इक्विटी बाजार में जुटाए गए संसाधनों के एक तिहाई से अधिक के लिए एलआईसी की सूचीबद्ध हुई।

**ऋण: सार्वजनिक ऋण जारी करने में कम सक्रियता निजी ऋण प्लेसमेंट द्वारा क्षतिपूर्ति से अधिक है**

4.35 अप्रैल-नवंबर 2022 में, प्राथमिक बाजार में ऋण प्रतिभूतियों को जारी करके जुटाए गए संसाधनों की मात्रा में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में निर्गमों की कुल संख्या में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल से नवंबर 2022 तक, ऋण के सार्वजनिक निर्गम में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 15 प्रतिशत की मामूली कमी देखी गई, और इसी अवधि में ऋण के सार्वजनिक निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि भी एक तिहाई से भी कम हो गई। हालांकि, सार्वजनिक ऋण जारी करने में कम सक्रियता निजी ऋण प्लेसमेंट द्वारा क्षतिपूर्ति से अधिक थी। निजी ऋण प्लेसमेंट की संख्या 851 से 945 तक 11 प्रतिशत बढ़ गई, जबकि अप्रैल-नवंबर 2022 में संसाधन जुटाए गए वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका 6: प्राथमिक बाजार से संसाधन जुटाना

विवरण	अप्रैल - नवम्बर 2021		अप्रैल - नवम्बर 2022	
	जारी करने की संख्या	राशि ( करोड़ )	जारी करने की संख्या	राशि ( करोड़ )
<b>क. इक्विटी</b>	<b>350</b>	<b>1,81,532</b>	<b>448</b>	<b>1,14,361</b>
आईपीओ	76	89,166	104	48,095
एफपीओ	0	0	1	4,300
निर्गम	18	22,659	37	3,436
क्यूआईपी	23	26,704	8	4,115
अधिमान्य आवंटन	233	43,004	298	54,414
<b>ख. ऋण</b>	<b>871</b>	<b>3,71,590</b>	<b>967</b>	<b>3,91,997</b>
जनता	20	9,132	22	6,624
निजी कार्य नियुक्ति	851	3,62,458	945	3,85,373
<b>कुल ( क+ख )</b>	<b>1,221</b>	<b>5,53,122</b>	<b>1,415</b>	<b>5,06,358</b>

स्रोत: सेबी

## द्वितीयक बाजार

### शेयर बाजार का निष्पादन: भारतीय शेयर बाजार में लचीला निष्पादन देखा जा रहा है

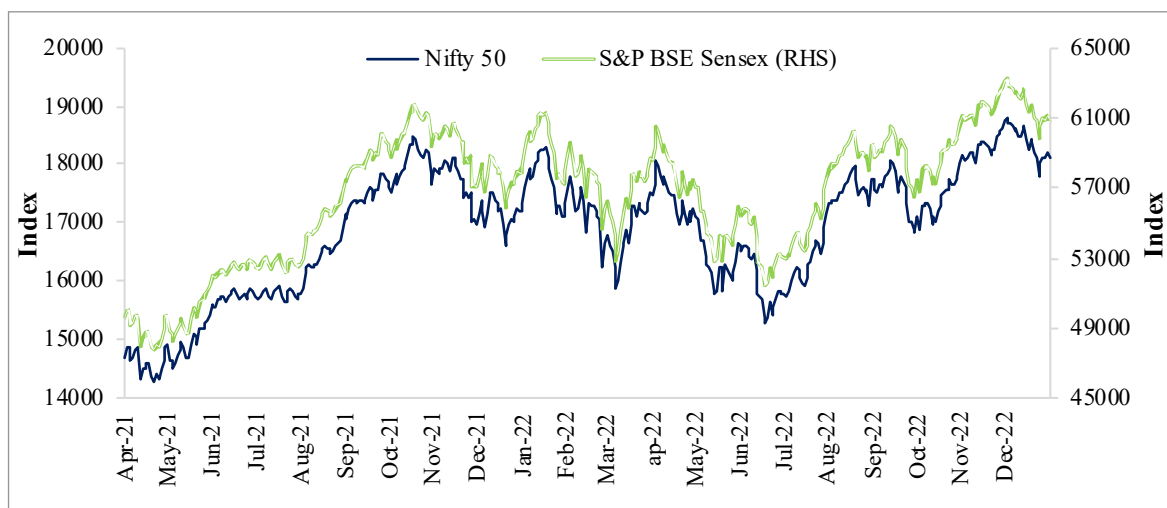
4.36 अप्रैल-दिसंबर 2022 में भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट आई। इसके विपरीत, भारतीय शेयर बाजार ने एक लचीला प्रदर्शन देखा, उसी अवधि के दौरान निफ्टी 50 ने 3.7 प्रतिशत की वापसी दर्ज की। निफ्टी 50-अमेरिकी डॉलर समायोजित प्रतिफल भी -4.7 प्रतिशत रहा, जो अमेरिकी डॉलर के प्रति भारतीय रुपये के मूल्यहास को समायोजित करता है। यूएस के संबंध में एसएंडपी 500 औसत सूचकांक में 15.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक कंपोजिट ख्र प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों के प्रति भारी भार (49 प्रतिशत) में 26.4 प्रतिशत की तेजी से गिरावट आई। दिसंबर 2022 के अंत में, सेंसेक्स दिनांक 31 मार्च, 2022 को अपने समापन स्तर से क्रमशः 3.9 प्रतिशत अधिक बंद हुए। प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भी, भारत ने अप्रैल-दिसंबर 2022 में अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया।

तालिका 7: वित्त वर्ष 2023 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान भारत ने अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया

सूची	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	30 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार	वित्त वर्ष 22 में प्रतिशत परिवर्तन (अप्रैल-नवंबर)	वित्त वर्ष 23 में प्रतिशत परिवर्तन (अप्रैल-दिसंबर)
<b>भारत</b>				
निफ्टी 50	17,464.7	18,105.3	18.1	3.7
एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स	58,568.5	60,840.7	17.7	3.9
<b>उभरते बाजार</b>				
शंघाई कम्पोजिट, चीन	3,252.2	3,089.3	5.8	-5.0
ब्राजील इबोवेस्पा	1,19,999.0	1,09,735.0	-10.1	-8.6
कोस्पी, कोरिया	2,757.6	2,236.4	-2.7	-18.9
<b>विकसित बाजार</b>				
नैस्डैक	14,220.5	10,466.5	18.1	-26.4
डॉव जोन्स, यूएसए	34,678.3	33,147.3	10.2	-4.4
एस एंड पी 500, यूएसए	4,530.4	3,839.5	20.0	-15.3
सीएसी, फ्रांस	6,659.9	6,473.8	17.9	-2.8
डैक्स, जर्मनी	14,414.8	13,923.6	5.8	-3.4
एफटीएसई 100, यूके	7,515.7	7,451.7	10.0	-0.9
हैंग सेंग, हांग कांग	21,997.8	19,781.0	-17.5	-10.1
निक्केई, जापान	27,821.4	26,094.5	-1.3	-6.2

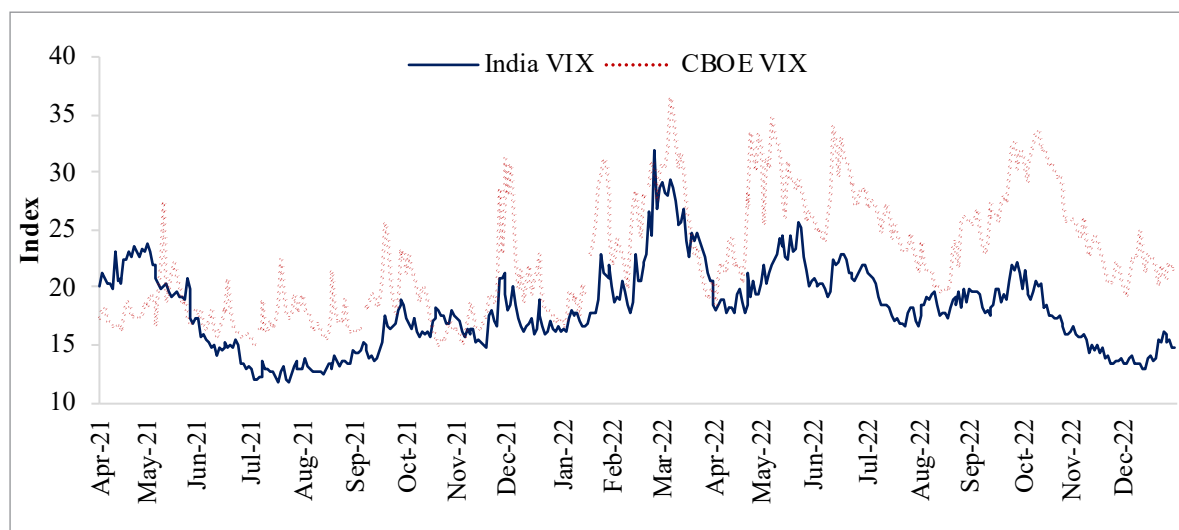
स्रोत: रिफिनिटिव, एनएसई, बीएसई

चित्र 20: भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों में तेजी से सुधार देखा गया



स्रोत: सेबी

चित्र 21: इंडिया वीआईएक्स में गिरावट का रुख देखा गया

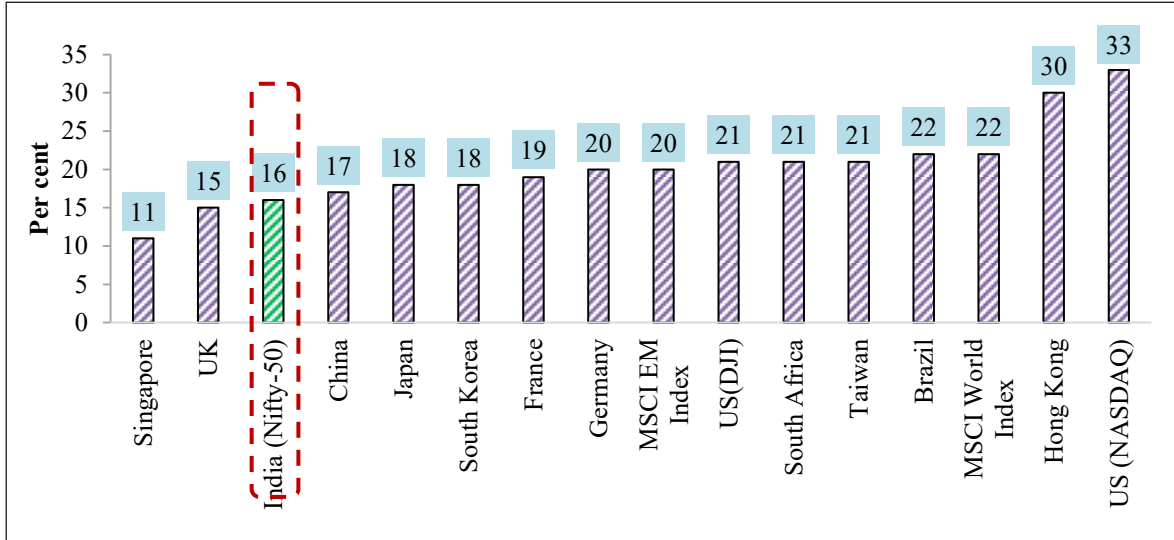


स्रोत: सेबी, ब्लूमबर्ग

नोट: VIX का मतलब अस्थिरता सूचकांक है। सीबीओई का मतलब शिकागो बोर्ड ऑफ़ॉस एक्सचेंज है

4.37 रूस-यूक्रेन संकट के बाद भू-राजनीतिक अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के कारण शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ गई। भारत VIX, जो शेयर बाजार में अल्पकालिक अस्थिरता को मापता है, 24 फरवरी 2022 को रूस-यूक्रेन संघर्ष के प्रकोप के साथ 32.0 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी इक्विटी बाजार (सीबीओई वीआईएक्स द्वारा मापा गया) में समान प्रवृत्ति देखी गई। संघर्ष के प्रकोप के बाद, भू-राजनीतिक संकट ने बाजार के रुझान को कमजोर कर दिया, जो कुछ हफ्ते में बेंचमार्क सूचकांकों के नीचे की ओर बढ़ने में परिलक्षित हुआ। भारतीय शेयर बाजार ने भी नुकसान दर्ज किया लेकिन जल्दी ही मार्च 2022 में एक सकारात्मक नोट पर समाप्त हुआ। अप्रैल-नवंबर 2022 में, भारत VIX में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई क्योंकि वर्ष बढ़ने के साथ संघर्ष का प्रभाव कम होने लगा।

चित्र 22: वित्तीय वर्ष 23 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान भारतीय सूचकांकों में वार्षिक अस्थिरता अपेक्षाकृत कम रही

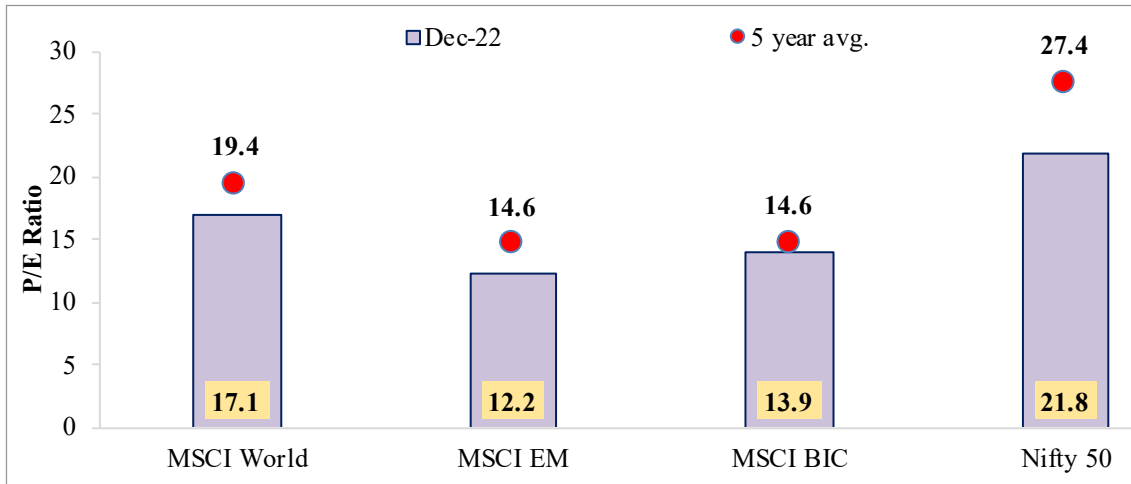


स्रोत: सेबी

### मूल्यांकन (पी/ई अनुपात): वैश्विक बाजारों की तुलना में निफ्टी 50

4.38 निफ्टी 50, दिसंबर 2022 के अंत में ट्रेलिंग आधार पर 21.8 गुना मूल्य-से-कमाई (पी/ई अनुपात) अनुपात के साथ, वैश्विक बाजारों की तुलना में महंगा है, हालांकि अभी भी अपने पिछले पांच साल के औसत की तुलना में कम है।

चित्र 23: निफ्टी 50 वैश्विक बाजारों की तुलना में महंगा है, हालांकि अपने 5 साल (2017-2021) के औसत की तुलना में अभी भी कम है



स्रोत: सेबी

टिप्पणियाँ: एम एससीआई वर्ल्ड इंडेक्स 23 विकसित बाजारों (डीएम) देशों में बड़े और मिड-कैप प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। एम एससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स 24 इमर्जिंग मार्केट्स (ईएम) देशों में बड़े और मिड कैप प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। एम एससीआई बीआईसी इंडेक्स एकपत्री लोट-एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेन वेटेड इंडेक्स है जिसे तीन इमर्जिंग मार्केट कंट्री इंडेक्स: ब्राजील, भारत और चीन में इक्विटी मार्केट के प्रदर्शन को मापने के लिए डिजाइन किया गया है।

### पूजी बाजार में खुदरा भागीदारी

4.40 वित्तीय वर्ष 22 के दौरान इसी अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 23 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान नकद खंड में व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई है। हालांकि, वर्ष दर वर्ष आधार पर नवंबर 2022

के अंत तक डीमैट खातों की संख्या में तेजी से 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, डीमैट खातों की वृद्धिशील वृद्धि चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचलित वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बीच संभवतः द्वितीयक बाजार में बढ़ी हुई अस्थिरता और प्राथमिक बाजार के कमजोर निष्पादन के कारण वित्तीय वर्ष 22 की तुलना में वित्त वर्ष 23 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति रही है।

**तालिका 8: इक्विटी कैश सेगमेंट टर्नओवर में व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी में गिरावट आई**

वर्ष	व्यक्तिगत निवेशकों का शेयर ( प्रतिशत )
वित्त वर्ष	41.1
वित्त वर्ष 22 (अप्रैल से नवंबर)	42.2
वित्त वर्ष 23 (अप्रैल से नवंबर)	37.5

स्रोत: एनएसई, बीएसई

नोट: व्यक्तिगत निवेशकों में व्यक्तिगत घरेलू निवेशक, एनआरआई, एकमात्र स्वामित्वफर्म और एचयूएफ शामिल हैं, अन्य: पार्टनरशिपफर्म/एलएलपी, ट्रस्ट/सोसायटी, डिपॉजिटरी रसीदें, सांविधिक निकाय, ओसीबी, एफएन, आदि।

**तालिका 9: वित्त वर्ष 2022 में डीमैट खातों में तेज वृद्धि देखी गई**

वर्ष	डीमैट खातों की कुल संख्या (लाख में)	अवधि के दौरान जोड़े गए खाते (लाख में)
वित्त वर्ष 22*	890.3	344.8
वित्त वर्ष 22@	766.1	220.7
वित्त वर्ष 23#	1,061.7	171.5

नोट: \*2022 मार्च के अंत में, @ नवंबर 2021 के अंत में, # नवंबर 2022 के अंत में

### टर्नओवर सांख्यिकी: इक्विटी व्युत्पन्न वॉल्यूम में भारी उछाल देखा गया

4.41 पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच नकदी खंड का कारोबार घट गया, जबकि इक्विटी व्युत्पन्नी मात्रा (वॉल्यूम) में काफी उछाल दर्ज किया गया, जो इक्विटी नकदी खंड से इक्विटी व्युत्पन्नी सेगमेंट में व्यक्तियों और मालिकाना व्यापारियों के बढ़ते हितों को दर्शाता है। दुनिया भर में व्याप्त भारी अनिश्चितता से प्रेरित, मुद्रा और कमोडिटी व्युत्पन्नी मात्रा (वॉल्यूम) में भी इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर्ज की गई।

**तालिका 10: इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी डेरिवेटिव्स में टर्नओवर सांख्यिकी में वृद्धि हुई**

Year	वित्तीय वर्ष- 22 (1)	वित्तीय वर्ष- 22# (₹ लाख करोड़) (2)	वित्तीय वर्ष- 23# (₹ लाख करोड़) (3)	प्रतिशत परिवर्तन (4)
नकद खंड	179.0	124.3	98.2	-21
इक्विटी व्युत्पन्नी	17,613.1	9,860.8	20,979.6	113
करेंसी व्युत्पन्नी	277.2	152.7	280.4	87
कमोडिटी व्युत्पन्नी	100.3	65.2	92.6	42
ब्याज दर व्युत्पन्नी	0.7	0.4	0.3	-17

स्रोत: सेबी

#अवधि-अप्रैल से नवंबर

### कमोडिटी व्युत्पन्न बाजार: फेड द्वारा मौद्रिक सख्ती के कारण तेज सुधार देखा गया

4.42 रूस-यूक्रेन संघर्ष ने वस्तुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, आधार धातुओं और खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न किया। परिणामस्वरूप, कच्चे तेल और निकेल और एल्युमीनियम जैसी कुछ बेस मेटल्स की कीमतों में अचानक उछाल देखा गया। हालांकि, बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए फेडरल रिजर्व द्वारा मार्च 2022 में ब्याज दरों में वृद्धि शुरू करने के कारण कमोडिटी की कीमतों में तेज सुधार देखा गया है। 31 मार्च 2022 की तुलना में नवंबर 2022 के अंत तक एमसीएक्सआई कॉमडेक्स बेस मेटल इंडेक्स की कीमत में 19.1 फीसदी की गिरावट आई, इसके बाद बुलियन इंडेक्स (-3.5 फीसदी) और एनर्जी इंडेक्स (-1 फीसदी) का नंबर आता है। एमसीएक्स पर एल्युमीनियम, कॉपर, जिंक और निकेल की कीमतों में भी नवंबर 2022 में 20 मार्च की तुलना में गिरावट दर्ज की गई।

### म्यूचुअल फंड में कम निवल प्रवाह देखा गया

4.43 अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान, म्यूचुअलफंड में पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम शुद्ध प्रवाह देखा गया। तथापि, इसी अवधि के दौरान, विकास/इक्विटी-उन्मुख योजनाओं और समाधान-उन्मुख योजनाओं वाली कुछ योजनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक अंतर्वाह देखा गया।

4.44 दूसरी ओर, आय/ऋण-उन्मुख योजनाओं और हाइब्रिड योजनाओं में पिछले वर्ष की समान अवधि में प्रवाह की तुलना में बहिर्वाह दर्ज किया गया। कॉर्पोरेट्स द्वारा ब्याज दर चक्र, नकदी आवश्यकताओं और अग्रिम कर प्रतिबद्धताओं में वृद्धि से मुख्य रूप से नकद निधियों और हाइब्रिड योजनाओं से बहिर्वाह प्रभावित हुआ। इसके बावजूद, बाजार के निष्पादन की बदौलत म्यूचुअलफंड उद्योग की संपत्ति प्रबंधन (एयूएम) में नवंबर 2022 के अंत में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका 11: म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम में वृद्धि

वर्ष	फोलियो संख्या ( करोड़ )	सकल संसाधन जुटाना ( लाख करोड़ )	मोचन ( लाख करोड़ )	शुद्ध संसाधन जुटाना ( लाख करोड़ )	एयूएम ( लाख करोड़ )
वित्तीय वर्ष 22	13.0	93.2	90.7	2.5	37.6
वित्तीय वर्ष 22#	11.7	58.6	56.1	2.5	37.3
वित्तीय वर्ष 23#	14.0	69.1	68.4	0.7	40.4

स्रोत: सेबी।

#संबंधित वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक

तालिका 12: इक्विटी-उन्मुख योजनाओं में शुद्ध प्रवाह देखा गया

वर्ष	आय/ऋण उन्मुख ( लाख करोड़ )	विकास/इक्विटी उन्मुख ( लाख करोड़ )	हाइब्रिड ( करोड़ )	समाधान उन्मुख ( करोड़ )	अन्य ( लाख करोड़ )	संपूर्ण ( लाख करोड़ )
वित्तीय वर्ष 22	2.0	-0.4	-2,936	1,577	0.6	2.1
वित्तीय वर्ष 22#	0.2	0.7	88,854	650	0.8	2.5
वित्तीय वर्ष 23#	-1.1	0.9	-13,649	1,091	1.0	0.7

स्रोत: सेबी।

नोट: अन्य योजनाओं में इंडेक्स निधि, गोल्ड ईटीएफ, अन्य ईटीएफ और विदेशों में निवेश करने वाले एफओएफ शामिल हैं।

#संबंधित वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक

## विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

### सुदृढ़ वृहद् आर्थिक आधार भारत एक आकर्षक गंतव्य बने सुनिश्चित करता है

4.45 वैश्विक आर्थिक कारकों, जैसे कि मुद्रास्फीति के दबाव, केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक दबाव, और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आशंकाओं ने एफपीआई पर भारतीय बाजारों में बिक्री के लिए दबाव डाला है। इसके अलावा, निवेशक भारतीय शेयरों के मुनाफा लिए बैठे थे, जिन्हें अन्यत्र ऑफसेट नुकसान के लिए साधित किया जा सकता था। बहरहाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ वृहद् आर्थिक आधार और समय-समय पर बाजार जोखिम की प्रवृत्ति में सुधार के कारण, संरक्षण प्राप्त संपत्ति (धारित के कुल बाजार मूल्य को दर्शाती एफपीआई की अभिरक्षण संबंधी धारित) में वैश्विक कारकों द्वारा संचालित बहिर्वाह के बावजूद वृद्धि देखी गई। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 के अंत में एफपीआई के पास संरक्षित कुल संपत्ति में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका 13: एफपीआई के तहत संरक्षित संपत्तियां में वृद्धि

वर्ष	इक्विटी (लाख करोड़)	ऋण (लाख करोड़)	ऋण वीआरआर (लाख करोड़)	हाइब्रिड (लाख करोड़)	संपूर्ण (लाख करोड़)
नवंबर 2022 को समाप्त	49.9	2.4	1.4	0.3	54.0
नवंबर 2021 को समाप्त	48.0	2.7	1.3	0.3	52.2

स्रोत: सेबी।

4.46 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा कुल शुद्ध निवेश में दिसंबर, 2021 के अंत में ₹. 5,578 करोड़ के प्रवाह से दिसंबर, 2022 के अंत में ₹. 16,153 करोड़ का प्रवाह दर्ज किया, इक्विटी खंड और ऋण खंड दोनों में शुद्ध एफपीआई बहिर्वाह देखा गया।

तालिका 14: एफपीआई में दर्ज बहिर्वाह के अनुसार शुद्ध निवेश

मासिक एफपीआई शुद्ध निवेश (वित्त वर्ष 23)					
माह	₹ करोड़				
	इक्विटी	ऋण	ऋण-वीआरआर	हाइब्रिड	कुल
अप्रैल	-17,144	-4,439	-1,175	69	-22,688
मई	-39,993	-5,506	9,043	-62	-36,518
जून	-50,203	-1,414	87	108	-51,422
जुलाई	4,989	-2,056	-785	-176	1,971
अगस्त	51,204	3,845	2,997	-1,525	56,521
सितंबर	-7,624	4,012	-1,455	1,112	-3,955
अक्टूबर	-8	-3,532	762	-301	-3,080
नवंबर	36,239	-1,637	-540	-214	33,847
दिसम्बर	11,119	-1,673	-272	-4	9,171
<b>कुल – FY23</b>	<b>-11,421</b>	<b>-12,400</b>	<b>8,662</b>	<b>-993</b>	<b>-16,153</b>

स्रोत: सेबी

\* ऊपर प्रस्तुत डेटा धारितों द्वारा सेबी/जमाकर्ताओं को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संकलित किया गया है और एफपीआई द्वारा पिछले ट्रेडिंग दिवस पर और उस तक किए गए ट्रेडों का गठन करता है।

# दिसम्बर 2022 तक।



4.47 भारत और चीन जैसे ईएमडीई से बड़े पूंजी प्रवाह, जो वस्तुओं के आयातक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्राजील जैसे वस्तु निर्यात उन्मुख बाजारों में प्रवाह से मेल खाते थे।

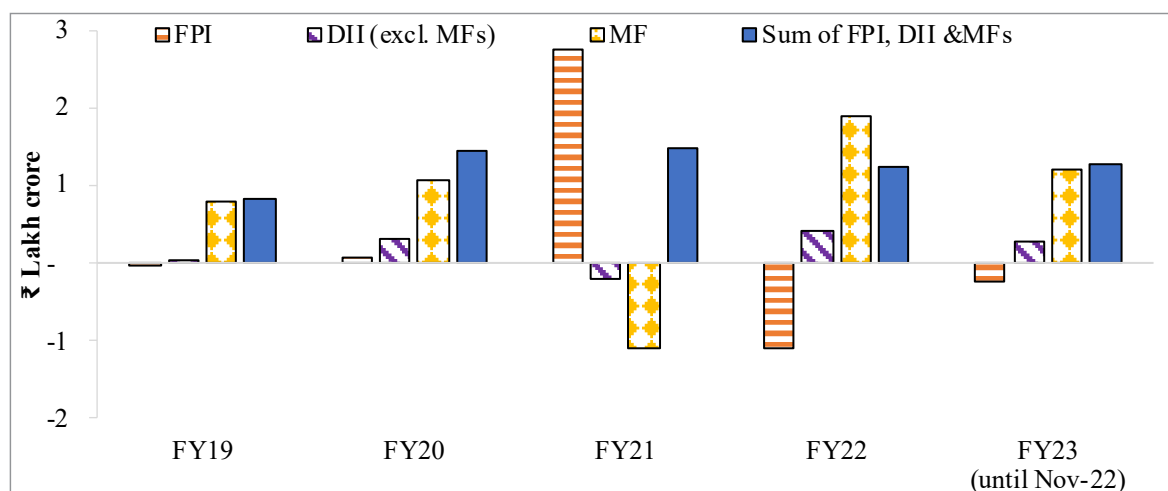
तालिका 15: चयनित बाजारों में कुल पोर्टफोलियो प्रवाह का रुझान ( बिलियन अमेरिकी डॉलर )

	2019	2020	2021	2022 ( नवंबर तक )
दक्षिण कोरिया	46.7	42.2	83.2	43.6
चीन	196.1	408.3	230.3	-183.3
ब्राजिल	-19.4	-6.4	14.6	3.1
जापान	88.9	-87.7	141.7	-39.0
भारत	17.7	9.5	2.2	-18.9
दक्षिण अफ्रीका	-10.2	-9.7	-23.6	-20.7
थाईलैंड	-2.0	-9.3	4.9	11.1
ताइवान	9.4	-15.3	-15.6	-41.5
तुर्की	-2.7	-9.4	0.4	-3.1

स्रोत: ब्लूमबर्ग, 12 दिसंबर, 2022 तक के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित

4.48 हाल के वर्षों के दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईई) के निवेशों की बराबर करने वाली प्रकृति ने एफपीआई बहिर्वाह के प्रति बराबर करने वाले बल के रूप में काम किया है, भारतीय इक्विटी ने बाजार को बड़े पैमाने पर सुधार के लिए अपेक्षाकृत कम संवेदनशील बना दिया है। वित्त वर्ष 23 (नवंबर 2022 तक) के दौरान इक्विटी में म्यूचुअलफंड द्वारा शुद्ध डीआईआई प्रवाह और शुद्ध निवेश देखा गया है।

चित्र 24: हाल के वर्षों के दौरान एफपीआई बहिर्गमन के लिए डीआईआई निवेश ने बराबर करने वाले बल के रूप में कार्य किया



स्रोत: सेबी

## अन्य विकास

क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करने के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण की आवश्यकता

4.49 क्रिप्टो एक्सचेंज फटीएक्स के हालिया पतन और क्रिप्टो बाजार में आगामी बिकवाली ने क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र की कमजोरियों पर प्रकाश डाला है। क्रिप्टो आस्तियां स्व-संदर्भित उपकरण हैं और वित्तीय संपत्ति होने की कसौटी

पर सख्ती से खारा नहीं उतरते हैं क्योंकि इसमें कोई आंतरिक नकदी प्रवाह नहीं है। अमेरिकी नियामकों ने बिटकॉइन, ईथर और विभिन्न अन्य क्रिप्टो आस्तियों को प्रतिभूतियों<sup>4</sup> के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है। फेडरल रिजर्व, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एफडीआईसी) और मुद्रा नियंत्रक कार्यालय (ओसीसी) द्वारा 3 जनवरी 2023 को एक असाधारण संयुक्त वक्तव्य<sup>5</sup> में बैंकिंग प्रणाली के लिए क्रिप्टो-एसेट जोखिमों के बारे में उनकी चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है। क्रिप्टो पारिस्थितिकी की भौगोलिक रूप से व्यापक प्रकृति इन अस्थिर उपकरणों के नियमन के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, क्रिप्टो के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया आ रही है, और बॉक्स 1 दुनिया भर में क्रिप्टो के लिए विनियामक दृष्टिकोण की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है।<sup>1</sup>

### बॉक्स 1: क्रॉस कंट्री विश्लेषण: क्रिप्टोकॉरेंसी का विनियमन

क्रिप्टो आस्ति क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों का उपयोग करके लागू की गई डिजिटल आस्ति के नए रूप हैं। क्रिप्टो आस्ति मार्केट बहुत अस्थिर रहा है, जिसका कुल मूल्यांकन बदलते हुए नवंबर 2021 में लगभग 3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बदले जनवरी 2023 में 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से कम हो गया है। क्रिप्टो एसेट पारिस्थितिकी की अस्थिरता ने उनके नाजुक समर्थन और शासन की समस्याओं के साथ-साथ बढ़ती जटिलता और गैर-पारदर्शिता को सबसे आगे ला दिया है। संबंधित वित्तीय स्थिरता जोखिम बढ़ने के साथ, क्रिप्टो आस्ति विनियमन के मुद्दे ने हाल ही में कई देशों के नीतिगत कार्यसूची को आगे बढ़ाया है। ओईसीडी और जी 20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच क्रिप्टो आस्ति को विनियमित करने के लिए विश्व स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण पर चर्चा कर रहे हैं।

#### क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण (बिलियन अमरीकी डॉलर)



स्रोत: : कोएनएमांआरकेटकेप

क्रिप्टोकॉरेंसी की निगरानी और विनियमन मुश्किल हो गया है, और दुनिया भर के नियामकों को तेजी से बढ़ते अज्ञात क्षेत्र में नए और उभरते मुद्दों पर नजर रखना चुनौतीपूर्ण लगता है। जबकि क्रिप्टो आस्तियाँ स्पष्ट रूप से पारंपरिक वित्तीय सेवाओं को विकेंद्रीकृत करने के लिए डिजाइन की गई थी, इसने नई अनियमित मध्यस्थ संस्थाओं का निर्माण किया है। विकेंद्रीकरण का वादा भी व्यवहार में अभी तक साकार नहीं हुआ है। नए केंद्रीकृत मध्यस्थ, जैसे कि क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज, वॉलेट प्रदाता और क्रिप्टो समूह, के उपयोगकर्ताओं को केंद्रीकृत संस्थाओं पर भरोसा करना अपेक्षित है। इन संस्थाओं का बढ़ता महत्व नियामकों को उन्हें प्रणालीगत वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)<sup>6</sup> के रूप में मानने के लिए मजबूर कर सकता है। फिर भी, तथ्य यह है कि वे अभी तक बड़े पैमाने पर अनियमित हैं, विश्व स्तर पर चिंता का कारण हैं।

1 बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अनुसार, फाइनेंशियल मार्केट क्रॉस-सेक्टर (फएमआई) को भाग लेने वाले संस्थाओं के बीच एक बहुपक्षीय प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सिस्टम के ऑपरेटर शामिल हैं, जिसका उपयोग समाशोधन, निपटान, या भुगतान, प्रतिभूति, डेरिवेटिव, या अन्य वित्तीय लेनदेन रिकॉर्ड करने के उद्देश्यों के लिए किया है। आरबीआई के अनुसार एफएमआई शब्द आम तौर पर व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों सेंट्रल सिक्नोरिटीज डिपॉजिटरीज (सीएमडी), सिक्नोरिटीज सिस्टम्स (एसएसएस), सेंट्रल काउंटर पार्टियों (सीसीपी) और ट्रेड रिपॉजिटरीज (टीआर) को संदर्भित करता है। जो वित्तीय लेनदेन की समाशोधन, निपटान और रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करता है।

दिलचस्प बात यह है, कि क्रिप्टो आस्तियां मुख्य रूप से कुछ “व्हेल” के हाथों में केंद्रित हैं। अनुमान बताते हैं कि सभी सर्कुलेटिंग बिटकॉइन का लगभग 85 प्रतिशत का 4.5 प्रतिशत संस्थाओं (बेन मरियम एट अल, 2020) के पास है। क्रिप्टो आस्तियां बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतर्निहित प्रोटोकॉल अन्य सार्वजनिक नीति उद्देश्यों उदाहरण के लिए, “खनन” क्रिप्टो संपत्ति की विशाल ऊर्जा तीव्रता के साथ भी विरोधाभास कर सकते हैं।

गैर-समर्थित क्रिप्टो आस्तियों पर न्यूनतम वैश्विक मानक लागू होते हैं, जो वर्तमान में सभी जोखिमों और अति संवेदनशीलता को कम नहीं करते हैं। यहां तक कि मानक-निर्धारण निकाय (एसएसबी) मानकों को समायोजित और विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से विशिष्ट मुद्दों (वित्तीय अखंडता), क्षेत्रों (भुगतान, प्रतिभूति और बैंकिंग), उत्पादों (वैश्विक स्थिर सिक्के), या घरेलू प्राधिकारियों द्वारा प्रणालीगत के रूप में नामित संस्थाओं पर केंद्रित हैं। इस प्रकार, जब गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा क्रिप्टो आस्तियों को जारी, स्थानांतरित, विनिमय, या संग्रहीत किए जाते हैं तब प्रत्येक चरण में विनियामक अंतराल होता है। क्रिप्टो का पार-क्षेत्र और सीमा-पार प्रकृति असंगठित राष्ट्रीय दृष्टिकोणों की प्रभावशीलता को सीमित करता है। विभिन्न गतिविधियों, उत्पादों और हितधारकों का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली षट्पावली विश्व स्तर पर सुसंगत नहीं है। ‘क्रिप्टो आस्तियां’ शब्द स्वयं ही डिजिटल उत्पादों के एक व्यापक विस्तार को संदर्भित करता है, जिसे उनके वास्तविक या भावी उपयोग के आधार पर कई घरेलू नियामकों के ध्यान की आवश्यकता हो सकती है। क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं की एक श्रृंखला है, जैसे कि माइनर, वैलिडेटर्स और प्रोटोकॉल डेवलपर्स, जो पारंपरिक वित्तीय विनियमन (नरैन और मोरेटी, 2022) द्वारा आसानी से कवर नहीं किए जा सकते हैं। गैर-समर्थित क्रिप्टो आस्तियों को विनियमित करने का प्रयास करने वाले देखें और न्यायालयों के कुछ मामलों के अध्ययन पर नीचे चर्चा की गई है:

\* यूरोपीय संघ: यूरोपीय संघ की डिजिटल वित्त रणनीति में क्रिप्टो आस्तियों (एमआईसीए) में बाजारों को विनियमित करना शामिल है। यहां तक कि अन्य क्रिप्टो आस्तियों और एक्सचेंजों तथा वॉलेट प्रदाताओं जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को वितरित करने वाली प्रमुख संस्थाओं के लिए स्थिर मुद्रा पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, एमआईसीए ऑनशोरिंग, अधिसूचना और लाइसेंस देने की व्यवस्था का प्रस्ताव करता है।

\* जापान: जापान वित्तीय सेवा एजेंसी ने अप्रैल 2017 में क्रिप्टो आस्तियां सेवा प्रदाताओं के विनियमन की शुरुआत की, जिसमें ग्राहकों की आस्तियों का पृथक्करण, संचालन जोखिम और साइबर सुरक्षा प्रबंधन, अपने ग्राहक को जानें, आंतरिक ऑडिट और न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं अनिवार्य हैं। यह भुगतान सेवा अधिनियम में संशोधन करके लागू किया गया था। मई 2019 और जून 2020 में कानून में और संशोधन किए गए ताकि क्रिप्टो विनियमन को अन्य संस्थाओं तक बढ़ाया जा सके, जैसे कि वॉलेट सेवा प्रदाता, क्रिप्टो आस्तियां एक्सचेंजों द्वारा खुदरा ग्राहकों को प्रदान किए गए लाभ को सीमित करना, और क्रमशः सुरक्षा टोकन और स्थिर मुद्रा के लिए नियम पेश करना।

जून 2022 में भुगतान सेवा अधिनियम आदि में आंशिक संशोधन के लिए कानून अधिनियमित किया गया था। ताकि एक स्थिर और कुशल निधि निपटान प्रणाली स्थापित किया जा सके और स्थिर सिक्कों के विनियमन के लिए प्रदान किया जा सके।

\*स्विट्जरलैंड: स्विस्फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी (एफआईएनएमए) ने फरवरी 2018 में प्रारंभिक सिक्के की पेशकश के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। टोकन की तीन श्रेणियां पेश की गईं: भुगतान टोकन, उपयोगिता टोकन, और आस्तियां टोकन (एक स्पष्टीकरण के साथ कि पूर्व वित्तपोषण पर व्यापार योग्य टोकन और पूर्व बिक्री चरण को प्रतिभूतियों के रूप में माना जा सकता है)। इसके बाद, जून 2018 में वित्तीय सेवा अधिनियम ने सभी प्रतिभूतियों (आस्तियां टोकन सहित) में विवरणिका की आवश्यकताओं को सुसंगत बनाया। फरवरी 2021 में वितरित खाता प्रौद्योगिकी (डीएलटी) ने विभिन्न नागरिक और वित्तीय बाजार कानूनों में संशोधन किया

ताकि ब्लॉकचेन पर खाता-आधारित प्रतिभूतियों की शुरुआत को सक्षम किया जा सके और क्रिप्टो धारितों के दिवालिया होने की स्थिति में क्रिप्टो आस्तियों के पृथक्करण के लिए नियम प्रदान करें।

\* यूनाइटेड किंगडम: जून 2019 में 'गइनेशियल कंडक्ट अथॉरिटी द्वारा 'क्रिप्टो आस्तियों पर अंतिम मार्गदर्शन' घोषित किया गया कि सुरक्षा टोकन ('निर्दिष्ट निवेश' के समान अधिकारों और दायित्वों के साथ क्रिप्टो आस्तियों) विनियामक दायरे में आते हैं, उपयोगिता और "एक्सचेंज टोकन" (अर्थात अनबैकड क्रिप्टो आस्तियां) विवेकपूर्ण और आचरण व्यवस्था के बाहर थे। क्रिप्टो आस्तियां बाजार पर महत्वपूर्ण उपभोक्ता अनुसंधान के बाद, अप्रैल 2022 में यूके ट्रेजरी ने क्रिप्टो आस्तियां विनियमन के लिए अपना रोडमैप तैयार किया है, जिसमें स्थिर मुद्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया और ब्लॉकचैन-आधारित एफएमआई के लिए सैंडबॉक्स व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया। क्रिप्टो आस्तियों के प्रचार-प्रसार को विनियमित करने के संबंध में, 2018 में यूके क्रिप्टो एसेट्स टास्कफोर्स<sup>8</sup> ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसमें पाया गया कि भ्रामक विज्ञापन (लाभों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना और शायद ही कभी खुदरा निवेशकों को अस्थिरता और जोखिमों की चेतावनी देना) और उपयुक्त जानकारी की कमी क्रिप्टो-आस्तियां बाजारों में महत्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण के मुद्दे थे। जनवरी 2022 में, यूके ट्रेजरी ने क्रिप्टो आस्तियों को अपने वित्तीय प्रचार व्यवस्था के भीतर लाने का प्रस्ताव दिया, क्रिप्टो आस्तियों के प्रचार को स्टॉक, शेयर और बीमा उत्पादों जैसे अन्य वित्तीय प्रचारों के समान उच्च मानकों के अध्वधीन किया है। इसी तरह, जनवरी 2022 सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने में सिंगापुर में क्रिप्टो आस्तियों के विपणन को प्रतिबंधित करने के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए, क्रिप्टो आस्तियों के प्रचार को कॉर्पोरेट वेबसाइट की एक इकाई, आधिकारिक सोशल मीडिया खातों और मोबाइल एप्लिकेशन तक सीमित कर दिया।

\* अल्बानिया: मई 2020 में अल्बानिया में निवेश उद्देश्यों के लिए 'डीएलटी-आधारित वित्तीय बाजार' (जिसे "फिनटोकन एक्ट" भी कहा जाता है) पर अल्बानिया का कानून क्रिप्टो आस्तियों को वैध करता है। विनियमन में डिजिटल टोकन और आभासी मुद्रा जारी करना और वितरण, व्यापार और संरक्षण में लगी संस्थाओं की लाइसेंसिंग, निगरानी और पर्यवेक्षण शामिल है। अल्बानियाई वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (एएफएसए) और नेशनल एजेंसीफॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी (एनआईएस) को अनबैकड क्रिप्टो एसेट्स (और बैंक ऑफ अल्बानियाफॉर स्टैब्लैक्स) के लिए सक्षम प्राधिकारियों के रूप में सौंपा गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि क्रिप्टो आस्तियां सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस देना तीसरे पक्ष के एजेंटों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जब एनआईएस द्वारा तकनीकी अनुपालन से निपटने के दौरान 'अभिनव सेवा प्रदाता' के रूप में एएफएसए द्वारा विनियामक और वित्तीय अनुपालन पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'डिजिटल टोकन एजेंट' के रूप में लाइसेंस दिया जाता है।

\* नाइजीरिया: फरवरी 2018 में सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया (सीबीएन) ने घोषित किया कि क्रिप्टो आस्तियां नाइजीरिया में कानूनी निविदा नहीं हैं। इसके अलावा, फरवरी 2021 में, सीबीएन ने विनियमित वित्तीय संस्थानों को लिखा है कि क्रिप्टो आस्तियों में व्यवहार करना और क्रिप्टो आस्तियां सेवा प्रदाताओं के लिए भुगतान की सुविधा प्रतिबंधित थी। अभी हाल ही में, मई 2022 में प्रतिभूति और विनियमन आयोग ने 'डिजिटल आस्तियों की पेशकश करने वाले प्लेटफॉर्म' और 'डिजिटल आस्तियों की पेशकश करने वाले धारक' पर मांग को लागू करने और एसईसी के दायरे में 'डिजिटल आस्तियां पेशकश' को रेखांकित करते हुए और "डिजिटल आस्तियों के परिणाम, पेशकश प्लैटफॉर्म और धारक पर नए नियम" प्रकाशित किया है।

एफएटीएफ द्वारा निर्धारित क्रिप्टो आस्तियों के प्रदाताओं के लिए एएमएल/सीएफटी दायित्वों के माध्यम से कुछ प्रगति के बावजूद उनका कार्यान्वयन अभी भी प्रगति पर है (एफएटीएफ 2021)<sup>9</sup>, 'यात्रा नियम' जैसे समीक्षात्मक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विलंब के साथ, आभासी आस्तियां (वीए) और आभासी आस्तियां सेवा प्रदाताओं (वीएसपी) क्षेत्र को आपराधिक और आतंकवादी दुरुपयोग<sup>10</sup> के लिए असुरक्षित छोड़ देता है। मार्च

2022 तक, जबकि 98 में से 29 उत्तर देने वाले न्यायालयों ने यात्रा नियम कानून पारित होने की सूचना दी, केवल 11 न्यायालयों ने प्रवर्तन और पर्यवेक्षी उपाय शुरू किए हैं। इसलिए, वैश्विक मानकों को व्यापक और सुसंगत होने की आवश्यकता है; विनियामक प्रतिक्रियाएं मानक वर्गीकरण पर आधारित होनी चाहिए, स्पर्श संचार प्रभावों को दूर करने के लिए विश्वसनीय डेटा, और भविष्य में बाजार के विकास और भविष्य के अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए।

## आईएफएससी - जीआईएफटी सिटी

4.50: पिछले कुछ वर्षों में, सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों ने पूंजी बाजार के खिलाड़ियों के लिए नए रास्ते और अवसर खोले हैं। जीआईएफटी सिटी में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) की स्थापना और संचालन सबसे महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य देश में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के एक मजबूत आधार के विकास को गति देकर भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने की सुविधा प्रदान करना है। नीचे दिया गया बॉक्स 2 प्रमुख भूमिका पर चर्चा करता है जो आईएफएससी भारत के विकास को और बढ़ावा देने के लिए पूंजी लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक पसंदीदा क्षेत्राधिकार के रूप में भारत के उद्भव को सुविधाजनक बनाने और विदेशी निवेशकों से आसान पहुंच और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने में निभा सकता है।

### बॉक्स 2: जीआईएफटी आईएफएससी - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक मुख्य अधिकार क्षेत्र के रूप में उभरना

विश्व स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों (आईएफसी) ने मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुखता ग्रहण की है क्योंकि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के विकास में वृहद पैमाने योगदान दिया है। इन केंद्रों ने वित्तीय वैश्वीकरण की गति को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आम बोलचाल में, एक आईएफसी वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों, स्टॉक मार्केट्स और संबंधित संस्थाओं, बीमाफर्मों, फंड मैनेजरों, फिनटेक फर्मों आदि के उच्च संकेंद्रण के साथ एक अधिकार क्षेत्र है, जो गैर-निवासियों और निवासियों को, ऐसे माहौल में जो वित्तीय नवाचार और सीमा पार लेनदेन की सुविधायुक्त विशेष वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, जीआईएफटी सिटी में भारत के पहले आईएफएससी की स्थापना और संचालन एक पथ-प्रवर्तक वित्तीय सुधार रहा है, जो पूंजी खाता परिवर्तनीयता के प्रति भारत के तेजी से उदार दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। जीआईएफटी-आईएफएससी विश्व स्तरीय वाणिज्यिक, सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के साथ भारत के पहले पूरी तरह से संचालित स्मार्ट सिटी है। आईएफएससी के विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 2019 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से आईएफएससी अर्थात् अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के लिए अपनी तरह का पहला, एकीकृत और चुस्त वित्तीय क्षेत्र नियामक स्थापित करने के लिए एक प्रमुख नीतिगत निर्णय लिया। दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से, जहां तक भारत में आईएफएससी के विकास और विनियमन का संबंध है, आईएफएससीए ने चार घरेलू क्षेत्र के नियामकों, अर्थात् आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीएआई की शक्ति ग्रहण की। पिछले दो वर्षों में, जीआईएफटी-आईएफएससी ने बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा, फंड प्रबंधन, विमान पट्टे पर देने आदि सहित वित्तीय सेवाओं के पूरे विस्तार में अतिबृहत् वृद्धि और संकर्षण के साथ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरेखित नियामक व्यवस्था, प्रतिस्पर्धी संरचना और संचालन की लाभकारी लागत के साथ जीआईएफटी-आईएफएससी अब अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक पसंदीदा क्षेत्राधिकार के रूप में उभर रहा है। आईएफएससी के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक, लंदन रिपोर्ट (मार्च 2022) ने जीआईएफटी सिटी में आईएफएससी को विश्व स्तर पर 15 केंद्रों में शीर्ष पर रखा है, जिसके अगले 2 से 3 वर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण होने की संभावना है।

जीआईएफटी-आईएफएससी में बैंक, पूंजी बाजार, बीमा, फिनटेक, एयरक्राफ्ट लीजिंग, शरफा बाजार आदि सहित वित्तीय सेवाओं के पूर्ण विस्तार में 390+ से अधिक संस्थाएं पंजीकृत हैं। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वित्तीय संस्थानों की स्वस्थ और बढ़ती भागीदारी के साथ वित्तीय सेवा बाजार तेजी से बढ़ रहा है।

### हाल के विकास/उपलब्धियाँ/नवाचार/अन्य देशों के साथ सहयोग

वैश्विक महत्ता का एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनने की अपनी दृष्टि के अनुसरण में आईएफएससीए कई विश्व स्तर पर प्रमुख वित्तीय प्राधिकरणों और मानक-निर्धारण निकायों के साथ लगातार विचार-विमर्श में लगा हुआ है। अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईएफएससीए द्वारा विदेशी नियामकों के साथ सहयोग को गहरा करने और जीआईएफटी-आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए सूचनाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान में सहायता के लिए 2 बहुपक्षीय समझौता ज्ञापनों (एमएमओयू) और 7 द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों (बीएमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। नीचे दी गई तालिका केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित समझौता ज्ञापनों की नवीनतम स्थिति प्रदान करती है-

#### बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमएमओयू)

- प्रतिभूति आयोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ)
- बीमा पर्यवेक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएआईएस)

#### द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (बीएमओयू)

- दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण (डीएफएसए)
- कतर वित्तीय सेवा प्राधिकरण (क्यूएफसीए)
- अबू धाबी ग्लोबल मार्केट (एडीजीएम) वित्तीय सेवा नियामक प्राधिकरण (एफएसआरए)
- फ्रांस के ऑटोराइट डेस मार्च फाइनेंसर्स (एएमएफ)
- कमीशन डी सर्विलांस डू सेक्टर फाइनेंसर (सीएसएसएफ) लक्समबर्ग
- फिनान्सिन्सपेक्टिओन (एफआई) स्वीडन।
- सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण (एमएस)

उपरोक्त के अलावा, आईएफएससीए ने आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं के लिए विश्व स्तरीय नियामक वातावरण के विकास के लिए तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण के लिए समझौते भी किए हैं। वैश्विक समुदाय के साथ आईएफएससीए के बढ़ते जुड़ाव को दर्शाने वाली कुछ परियोजनाएँ/समझौते पर नीचे प्रकाश डाला गया है:

### सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ फिनटेक ब्रिज

भारत और सिंगापुर दोनों फिनटेक क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। फिनटेक विकास के अगले चरण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार जीआईएफटी-आईएफएससी को सभी फिनटेक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएस) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने एक संयुक्त नियामक सैंडबॉक्स सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक में नियामक सहयोग और साझेदारी की सुविधा के लिए फिनटेक सहयोग समझौते (सीए) पर हस्ताक्षर किए हैं जो प्रौद्योगिकी नवाचारों के प्रयोग का समर्थन करने के लिए अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में मौजूदा नियामक सैंडबॉक्स का लाभ उठाएगा। यह समझौता फिनटेकफर्मों को एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार में एक नियामक रेफरल प्रणाली के माध्यम से बाजार पहुंच प्राप्त करने में सक्षम करेगा।

### एनएसई आईएफएससी -एसजीएक्स कनेक्ट

एनएसई-आईएफएससी - एसजीएक्स कनेक्ट, जिसका 29 जुलाई, 2022 को प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, पूंजी बाजार के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कनेक्ट को, जून, 2023 तक पूरी तरह से चालू करने की संभावना है, एसजीएक्स, सिंगापुर से एनएसई-आईएफएससी, जीआईएफटी सिटी के लिए निफ्टी उत्पादों में ऑनशोरिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कनेक्ट से जीआईएफटी आईएफएससी में डेरिवेटिव उपकरणों में मात्रा को मजबूत करने और नकदी को गहरा करने, अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को लाने और जीआईएफटी-आईएफएससी में अन्य वित्तीय पारिस्थितिक तंत्रों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की संभावना है। इसे संबंधित एक्सचेंजों के लाभों का उपयोग करने के लिए, निवेशकों तक आसानी से पहुंच के लिए एसजीएक्स और सभी को लाभ प्रदान करने के लिए सहजीवी तरीके से व्युत्पन्न अनुबंधों के व्यापार तथा समाशोधन के लिए एनएसई आईएफएससी को डिजाइन किया गया है।

### विश्व स्तर पर फिनटेक के बीच सह्यता और मन की बात

जीआईएफटी-आईएफएससी में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और वैश्विक फिनटेक समुदाय के बीच दृश्यता बनाने के लिए, आईएफएससी ने भारत सरकार के समर्थन से, 2021 से शुरू होने वाली वार्षिक विशेषता के रूप में एक प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी और वैश्विक विचार नेतृत्व कार्यक्रम, 'इन्फिनिटीफोरम' की स्थापना की है। यह चर्चा करने और कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी में दुनिया के अग्रणी दिमाग को एकजुट करता है कि कैसे फिनटेक उद्योग समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठा सकता है। 3 और 4 दिसंबर 2021 को आयोजित फोरम के पहले संस्करण का उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था, जिसमें इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम भागीदार देशों के रूप में भाग ले रहे थे। इस आयोजन में कुल 94,300 पंजीकरण हुए, जिसने एक बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय पदचिह्न को पीछे छोड़ दिया।

### इंडिया आईएनएक्स और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच सहयोग समझौता

01 जून, 2022 को आईएफएससी-आधारित एक्सचेंज इंडिया आईएनएक्स ने लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोनों एक्सचेंज एल्यूएक्सएसई पर सूचीबद्ध ऐसी प्रतिभूतियों के प्रवेश की सुविधा देकर अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के प्रति सूचीबद्ध भारतीय प्रतिभूतियों की दृश्यता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नवंबर 2020 में यह समझौता दोनों संस्थानों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर आधारित है, जो भारत में हरित वित्त को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। इंडिया आईएनएक्स और एल्यूएक्सएसई के बीच इस दोहरी सूचीबद्ध सहयोग समझौते के साथ स्थापित ग्रीन कॉरिडोर अवसर भारती और उसके क्षेत्र से अधिक जारीकर्ताओं को आकर्षित करने और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से हरित पूंजी तक पहुंच प्रदान करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

### वित्तीय वर्ष 2024 और उसके बाद के लिए आईएफएससीए विजन

वित्त वर्ष 2023 आईएफएससी के लिए एक ऐतिहासिक घटना वर्ष है। यह भारत को प्रथम आईएफएससी दशक को चिह्नित करता है। 2022 से आगे की दृष्टि योजना जीआईएफटी-आईएफएससी को नए युग की वैश्विक वित्तीय सेवाओं और गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में एक गुणी आत्मनिर्भर प्रक्षेपवक्र तक बढ़ाने के इर्द-गिर्द घूमती है। वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने की यह महत्वाकांक्षी खोज सीखने में समृद्ध रही है जिसे केंद्र को वित्तीय नवाचार और गतिशीलता की उच्च क्षेत्र में ले जाने के लिए अत्याधुनिक वैधानिक और नियामक ढांचे को डिजाइन करने

के लिए व्यवस्थित रूप से पूंजीकृत किया जा रहा है। जीआईएफटी-आईएफएससी अपनी स्थापना वर्षों के भीतर भारत में वैश्विक पूंजी के प्रवाह के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार बन गया है। शर्माफा व्यापार, एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग, ग्लोबल-इन हाउस सेंटर्स, फिनटेक, सस्टेनेबलफाइनेंसिंग और पार देश बिल डिस्काउंटिंग और फैंक्टरी निर्माण जैसी प्रायोगिक और अभिनव वित्तीय सेवाओं को शुरू करने में महत्वपूर्ण लाभ हुआ है। परिष्कृत वित्तीय उत्पाद जैसे शर्माफा डिपॉजिटरी रसीदें, अप्रयोजित डिपॉजिटरी रसीदें, और वित्तीय और परिचालन पट्टे पेश किए गए हैं, और भी कई कतार में हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी, एकीकृत आवासीय परियोजनाओं, सेंट्रल पार्क, रिवरफ्रंट और मनोरंजक केंद्रों सहित आवश्यक परियोजनाओं के साथ जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता के लिए अत्याधुनिक अवसंरचनाएं तैयार की गई हैं।

घरेलू विनियमों से मुक्त आईएफएससी में छूट देकर विदेशी विश्वविद्यालयों को संचालन स्थापित करने की अनुमति देकर एक संपन्न ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने की नींव रखी गई है। इसके साथ ही, जीआईएफटी सिटी में भारत के प्रमुख फिनटेक संस्थान और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए बाहरी सहायता जुटाई जाती है। केंद्र, ₹ 800 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ, फिनटेक में भारत के बढ़ते कद और नेतृत्व को मजबूत करेगा और विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करेगा।

गौरतलब है कि जीआईएफटी-आईएफएससी के लिए सरकार का दृष्टिकोण पारंपरिक वित्त और उद्यम से कहीं आगे बढ़कर वैचारिक नेतृत्व करता है। इसे सरलता और नवीनता के केंद्र, आत्म निर्भर भारत के अवतार के रूप में देश गया है। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, दृष्टिकोण के बारे में कल्पना में एक लंबी छलांग लगाता है और जीआईएफटी सिटी को एक हलचल भरे वित्तीय केंद्र में बदलने का प्रयास करता है, एक व्यवसायिक ग्राहक जो एक विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय चरित्र रखता है और वित्त से जुड़ी जटिल समस्या बयानों का अग्रणी समाधान है।

## बीमा बाजार में विकास

### वैश्विक स्तर पर बीमा बाजारों ने महामारी के प्रभाव पर काबू पाने में उल्लेखनीय लचीलेपन और लचीला निष्पादन किया है

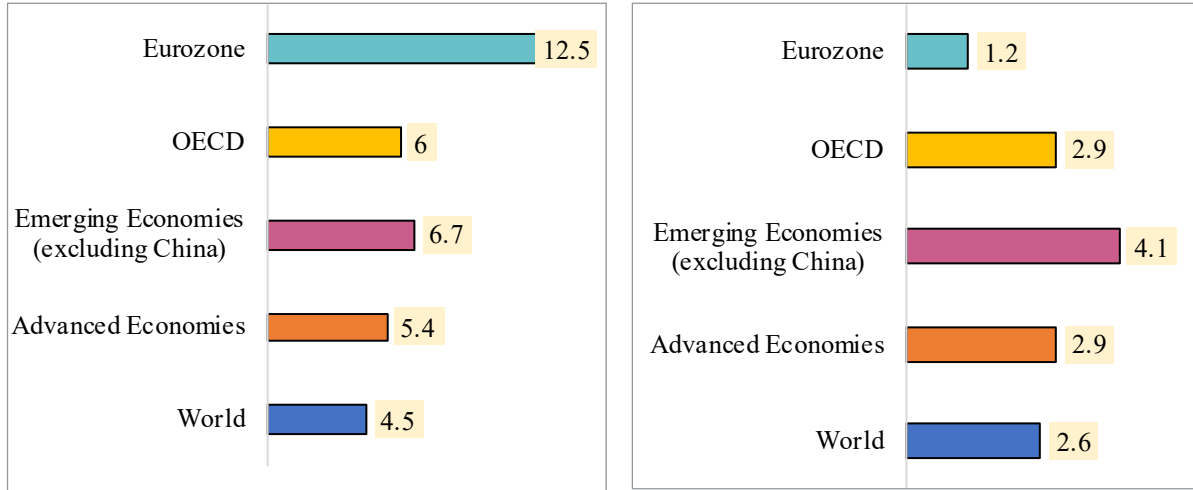
4.51 बीमा, वित्तीय क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है, जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृत्यु दर, संपत्ति और हताहत जोखिमों से सुरक्षा और सुरक्षा जाल प्रदान करने के अलावा, बीमा क्षेत्र बचत को प्रोत्साहित करता है और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक धन प्रदान करता है। इसके निरंतर आर्थिक परिवर्तन का समर्थन करने के लिए बीमा क्षेत्र का विकास आवश्यक है।

4.52 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बीमा क्षेत्र की क्षमता और प्रदर्शन का आकलन आम तौर पर दो मापदंडों के आधार पर किया जाता है, जैसे, बीमा प्रवेश, जो एक वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए कुल बीमा प्रीमियम के अनुपात और 'बीमा घनत्व' को संदर्भित करता है, जो जनसंख्या के लिए बीमा प्रीमियम के अनुपात को संदर्भित करता है, अर्थात्; प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम और अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है, क्योंकि वे किसी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर को दर्शाते हैं। 2021 में, कुल वैश्विक बीमा प्रीमियम में वास्तविक रूप से 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो विकसित बाजारों में वाणिज्यिक लाइनों में सख्त दर से प्रेरित थी। हालांकि, चीन में, सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार, गैर-जीवन



प्रीमियम वॉल्यूम 0.7 प्रतिशत तक सिकुड़ गया क्योंकि मोटर बीमा के डी-टैरिफिकेशन<sup>11</sup> ने भयंकर प्रतिस्पर्धा और दर में कटौती को बढ़ावा दिया।

**चित्र 25क: 2021 में जीवन-बीमा प्रीमियम की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन**      **चित्र 25ख: 2021 में गैर-जीवन बीमा प्रीमियम की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन**



स्रोत: स्विस रे, सिग्मा विभिन्न मुद्दे

4.53 जीवन बीमा खंड में, वैश्विक प्रीमियम वृद्धि ने 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए जोरदार वापसी की। 2021 में यूएस + 2.8 ट्रिलियन के कुल प्रीमियम (गैर-जीवन और जीवन) के साथ अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बीमा बाजार बना रहा, इसके बाद चीन और जापान का स्थान रहा। विशेष रूप से यूरोप में यूक्रेन में संघर्ष आर्थिक विकास पर भार के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि उभरते हुए बाजारों में बीमा उद्योग की वृद्धि इस साल विकसित बाजारों से आगे निकल जाएगी, जिसमें उभरता हुआ एशिया प्रमुख होगा।

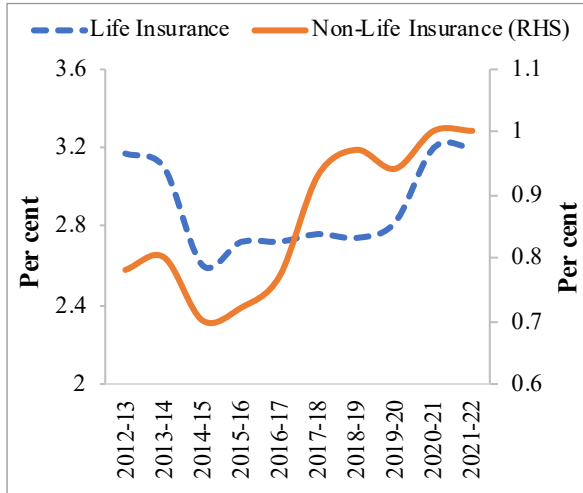
### भारत आने वाले दशक में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है

4.54: 2020 में सहस्राब्दी के मोड़ के आसपास भारत में बीमा प्रवेश 2.7 प्रतिशत से लगातार बढ़कर 4.2 प्रतिशत हो गई और 2021 में समान रही। 2021 में भारत में जीवन बीमा की प्रवेश 3.2 प्रतिशत थी, जो उभरते बाजारों से लगभग दोगुनी और वैश्विक औसत से थोड़ी अधिक थी। तथापि केवल एक छोटे से सुरक्षा घटक के साथ भारत में बेचे जाने वाले अधिकांश जीवन बीमा उत्पाद बचत से जुड़े होते हैं। इसलिए, प्राथमिक अर्जक की समय से पहले मृत्यु होने की स्थिति में परिवारों को एक महत्वपूर्ण वित्तीय अंतर का सामना करना पड़ता है। भारत में बीमा घनत्व 2001 में 11.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 में 91 अमेरिकी डॉलर हो गया है (जीवन बीमा के लिए घनत्व 69 अमेरिकी डॉलर था और गैर-जीवन बीमा 2021 में 22 अमेरिकी डॉलर था)।

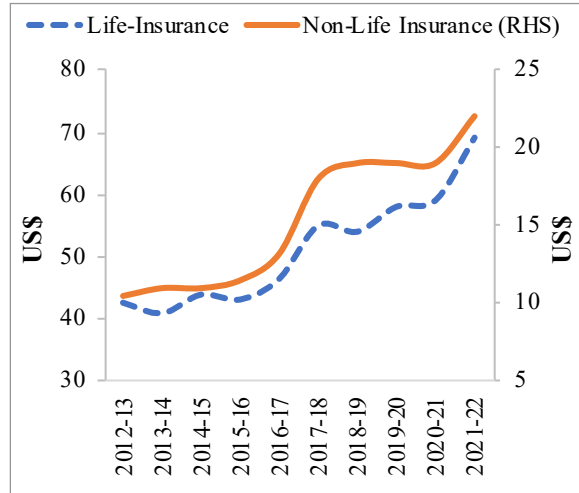
4.55 वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, गैर-जीवन बीमाकर्ताओं (भारत के भीतर और बाहर) के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम में 10.8 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य और मोटरफंड द्वारा संचालित है। वित्त वर्ष 2022, में गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का निवल दावा ₹ 1.4 लाख करोड़ था, जो मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय, उत्पाद नवाचारों और अनुकूलन, मजबूत वितरण चैनलों के विकास और बढ़ती वित्तीय साक्षरता से प्रेरित था। वित्त वर्ष 2022 में जीवन बीमा प्रीमियम में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें नए व्यवसायों

का योगदान जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम का 45.5 प्रतिशत था। जीवन बीमा उद्योग ने वित्त वर्ष 2022 में 5.02 लाख करोड़ रुपये का लाभ दिया, जिसमें से 8.3 प्रतिशत लाभ मृत्यु दावों पर थे।

चित्र 26क: बीमा प्रवेश में लगातार वृद्धि



चित्र 26ख: बीमा घनत्व में दो अंकों की वृद्धि



स्रोत: स्विस रे, सिग्मा विभिन्न मुद्दे

4.56 सार्वजनिक लिस्टिंग सार्वजनिक प्रकटीकरण, कॉर्पोरेट प्रशासन और मूल्यांकन में सुधार करती है। इस समझ के अनुरूप, भारत का सबसे बड़ा जीवन बीमाकर्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम, मई 2022 में सार्वजनिक हुआ, जिसने देश के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ में 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। निजी बीमा प्रदाता भी ऐसे अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनी स्टार हेल्थ और एलाइड इश्योरेंस को दिसंबर 2021 में सूचीबद्ध किया गया था, जिससे यह आईपीओ में निजी क्षेत्र की पांचवीं बीमा कंपनी बन गई। सार्वजनिक लिस्टिंग सार्वजनिक प्रकटीकरण, कॉर्पोरेट प्रशासन और मूल्यांकन<sup>12</sup> में सुधार करती है। बीमा क्षेत्र अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और पहले से ही विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) गतिविधि देख रहा है क्योंकि बीमाकर्ताओं के पास अंतरिक्ष में सह-अस्तित्व के लिए जबरदस्त अवसर और मात्रा है। अतिरिक्त एफडीआई प्रवाह, आईपीओ, सरलीकृत नियम और विनियम और बेहतर कॉर्पोरेट मूल्यांकन से क्षेत्र में एम एंड ए गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। तेजी से परिपक्व हो रहे बीमा बाजार ने सरकार को बीमा कारोबार में अपनी हिस्सेदारी का निजीकरण करने का आकर्षक अवसर प्रदान किया है। तदनुसार, सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 केंद्र सरकार को एक निर्दिष्ट बीमाकर्ता में इक्विटी पूंजी के 51 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी को कम करने की अनुमति देता है।

4.57 जनसंख्या के निम्न आयफंड को बीमा प्रवेश की सुविधा देने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 जारी किया, जो ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए वहनीय बीमा उत्पादों के वितरण के लिए एक मंच प्रदान करता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमाकर्ताओं की बाध्यताएं) विनियम, 2015 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में बीमाकर्ताओं के लिए दायित्वों को निर्धारित करता है और इसने भारत में सूक्ष्म-बीमा उत्पादों को विकसित करने और बढ़ावा देने में योगदान दिया है। वित्त वर्ष 2021 में, 10.7 लाख नई माइक्रो-बीमा पॉलिसी व्यक्तियों को ₹ 355.3 करोड़ (जीवन-बीमा खंड में) के नए व्यावसायिक प्रीमियम के साथ जारी की गईं, और 53,046 नई माइक्रो-बीमा पॉलिसियाँ सामान्य बीमा खंड (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता को छोड़कर) में जारी की गईं।

4.58 सरकारी योजनाओं और वित्तीय समावेशन की पहलों ने बीमा अपनाने और सभी क्षेत्रों में पैठ बनाने में मदद की है। फसल बीमा के लिए सरकार की प्रमुख पहल, प्रधानमंत्रीफसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) नेफसल बीमा के लिए प्रीमियम आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) (एबी पीएम-जेएवाई) का लक्ष्य माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹ 5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। बीमा नियामक आईआरडीएआई ने बीमा पैठ बढ़ाने की दिशा में कई पहल की हैं, जैसे कि बीमाकर्ताओं को वीडियो-आधारित नो योर कस्टमर (केवाईसी) आयोजित करने की अनुमति देना, मानकीकृत बीमा उत्पादों को लॉन्च करना और बीमाकर्ताओं को कम जोखिम वाले व्यवहार के लिए पुरस्कार की पेशकश करने की अनुमति देना। महत्वपूर्ण सरकारी पहलों, मजबूत जनसांख्यिकीय कारक, एक अनुकूल नियामक वातावरण, एम एंड ए में वृद्धि, उत्पाद नवाचार और जीवंत वितरण चैनल बीमा बाजार के विकास का समर्थन कर रहे हैं।

विभिन्न सरकारी बीमा योजनाओं की सूची और अब तक हुई प्रगति नीचे तालिका में दी गई है:

**तालिका 16: सरकारी बीमा योजनाएं और प्रगति**

योजना का नाम	संक्षिप्त विवरण	उपलब्धि
आयुष्मान भारत योजना	यह योजना चुनिंदा अभावों और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर पहचान किए गए गरीब और कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी परिवार को ₹ 5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।	स्थापना के बाद से, 19.7 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए हैं, और 20 जनवरी, 2023 तक 13,115 निजी अस्पतालों सहित 28,667 सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से ₹ 4.3 करोड़ से अधिक अस्पताल में ₹ 0.49 लाख करोड़ मूल्य से अधिक को प्रवेश के लिए अधिकृत किया गया है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	इस योजना के तहत, लाभार्थियों को आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए ₹ 2 लाख और आंशिक विकलांगता के लिए ₹ 1 लाख का जोखिम कवरेज दिया जाता है।	इसकी स्थापना के बाद से, 31.3 करोड़ लाभार्थियों को योजना के तहत नामांकित किया गया है, और 30 नवंबर 2022 तक 1.07 लाख दावों का वितरण किया गया है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	योजना के तहत, बीमाधारक की मृत्यु के मामले में धारक के बचत बैंक खाते में ₹ 2 लाख का जोखिम कवरेज जमा किया जाता है।	इसकी स्थापना के बाद से, 14.4 करोड़ लाभार्थियों को योजना के तहत नामांकित किया गया है, और 30 नवंबर 2022 तक 6.3 लाख दावों का वितरण किया गया है।

प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना	इस योजना के तहत, एलआईसी को सरकारी गारंटी के आधार पर सदस्यता राशि से जुड़ी सुनिश्चित पेंशन/वापसी के प्रावधान के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान की जाती है।	30 सितंबर 2022 तक इन ग्राहकों द्वारा जमा की गई ₹ 84,659.4 करोड़ की सब्सक्रिप्शन राशि के साथ कुल 8.6 लाख सब्सक्राइबर इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्रीफसल बीमा योजना	इस योजना के तहत, संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचितफसलों/क्षेत्रों के लिए पूर्व-बुवाई से लेकर कटाई के बाद के गैर-रोकथाम प्राकृतिक जोखिमों के कारण किसानों को फसल क्षति के लिए जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है।	वर्ष 2016 और वर्ष 2022 के दौरान, योजना के तहत 2763.9 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, और किसानों को लगभग 1.28 लाख करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।

स्रोत: डीएफएस, पीआईबी, पीएमएफबीवाई

4.59 मुद्रास्फीति के दबाव, आर्थिक अनिश्चितता और मौद्रिक तंगी से चल रही महामारी के कारण पिछले साल की मजबूत रिकवरी के बाद वैश्विक जीवन प्रीमियम 2022 में थोड़ा कम होने की संभावना है। वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और प्रयोज्य आय में गिरावट के कारण बचत प्रीमियम में गिरावट की उम्मीद है। कोविड-19 के कारण बढ़ी हुई जोखिम जागरूकता जीवन सुरक्षा (और स्वास्थ्य) बीमा उत्पादों की मांग का समर्थन करना जारी रख सकती है।

4.60 स्विस रे इंस्टीट्यूट वर्ल्ड इंश्योरेंस: 'मुद्रास्फीति जोखिम सामने और केंद्र रिपोर्ट'<sup>13</sup> के अनुसार, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक है। कुल प्रीमियम मात्राओं में, यह वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर 10वां सबसे बड़ा था, जिसकी अनुमानित बाजार हिस्सेदारी 1.9 प्रतिशत थी और जो सभी उभरते बाजारों में दूसरा सबसे बड़ा था। जर्मनी, कनाडा, इटली और दक्षिण कोरिया से आगे, भारत के 2032 तक दुनिया के शीर्ष छह बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने की उम्मीद है। इसके अलावा, गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में वृद्धि स्वास्थ्य कवरेज की मांग से प्रेरित होने की संभावना है, क्योंकि लोग कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूक हैं और सरकार द्वारा प्रायोजित जन स्वास्थ्य कार्यक्रम (आयुष्मान भारत) से मजबूत समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। अनिवार्य मोटर थर्ड-पार्टी बीमा कई गुना बढ़ जाएगा क्योंकि जैसे-जैसे भारत का मध्यम वर्ग बदला है और अधिक कारें खरीदता है।

4.61 भारत के बीमा बाजार का डिजिटलीकरण टेलीमैटिक्स और ग्राहक जोखिम मूल्यांकन से परे है। हाल के वर्षों में कई डिजिटल प्लेटफॉर्म उभरे हैं, जो बीमा खरीद सहित विभिन्न सेवाओं की पेशकश करते हैं। बीमा कंपनियों के लिए एफडीआई सीमा में वृद्धि के साथ-साथ इन उपायों से दीर्घकालिक पूंजी, वैश्विक प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रवाह में वृद्धि की संभावना है, जो भारत के बीमा क्षेत्र के विकास का समर्थन करेगा।

## पेंशन क्षेत्र

### कोविड-19 के दौरान भारत के पेंशन क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया

4.62 पेंशन प्रणाली का ढांचा विश्व स्तर पर विकसित हुआ है। उन्नत देशों में, पेंशन क्षेत्र पर्याप्त है, आंशिक रूप से औपचारिक वेतनभोगी रोजगार के एक बड़े हिस्से से उपजा है। जबकि राज्य कुछ मूल पेंशन प्रदान करता है, यह केवल कभी-कभी वित्त पोषित होता है और इस प्रकार पेंशन भुगतान के लिए वर्तमान सरकारी राजस्व

<sup>16</sup> <https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2170>

पर निर्भर उपयोगानुसार भुगतान करें वाली योजना है। वर्ष 2021 में, ओईसीडी देशों में पेंशन आस्तियां 14 38.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो सकल घरेलू उत्पाद का 66.9 प्रतिशत थी। कुछ ओईसीडी देशों में, पेंशन आस्तियां सकल घरेलू उत्पाद के 100 प्रतिशत से अधिक थीं। यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेंशनफंड में सबसे बड़ी हिस्सेदारी दर्ज की। कोविड-19 के दौरान, देशों ने स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने, श्रम बाजारों पर संकट के प्रभाव को सीमित करने, आय का समर्थन करने और व्यापक आर्थिक नीतियों को समायोजित करने के लिए अभूतपूर्व और तेजी से स्वास्थ्य और पेंशन संबंधी सुधार<sup>15</sup> किए।

4.63 दुनिया भर के देशों ने हाशिए पर पड़े, गरीब और कमजोर वर्गों पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए पेंशन क्षेत्र में सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की, जैसे नौकरी प्रतिधारण योजना (जेआरएस) के माध्यम से मजदूरी और पेंशन पात्रता में सब्सिडी देना, बेरोजगारी लाभों तक पहुंच को व्यापक बनाना, या श्रमिकों के नए समूहों को बेरोजगारी बीमा प्रदान करना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वरोजगार के लिए बेरोजगारी लाभों के कवरेज का विस्तार किया और फिनलैंड ने स्वरोजगार के लिए पहले से मौजूद योजना के कवरेज को व्यापक बनाया। चिली ने श्रमिकों के लिए बेरोजगारी बीमा के कवरेज का स्थायी रूप से विस्तार किया। न्यूजीलैंड ने उन कर्मचारियों के लिए तीन महीने तक के लिए अस्थायी लाभ का भुगतान किया, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी और स्व-नियोजित उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी गतिविधि बंद कर दी।

4.64 भारत सरकार ने कोविड के कारण अपने कमाने वाले सदस्यों को खोने वाले परिवारों को पेंशन प्रदान करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की। इसने बीमा मुआवजे को बढ़ाने और उदार बनाने की दिशा में भी पहल की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) पेंशन योजना का लाभ उन लोगों को भी दिया गया जिन्होंने कोविड-19 के कारण कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है। ऐसे व्यक्तियों के आश्रित परिवार के सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार श्रमिक द्वारा प्राप्त औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन के हकदार थे। कर्मचारी जमा लिंकड बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत बीमा लाभों को भी बढ़ाया और उदार बनाया गया।

4.65 अप्रैल-जून 2020 के दौरान तीन महीने के लिए लगभग तीन करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और आबादी के विकलांग वर्गों (60 वर्ष से अधिक आयु) को ₹ 1,000 की अनुग्रह राशि दी गई। सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 64, 1972, अभूतपूर्व महामारी के बीच पेंशन लाभों की तत्काल अर्न्तम मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए ढील दी गई थी। केंद्र सरकार के सिविल पेंशन भोगियों के 'जीवनयापन की सुगमता' को बढ़ाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ई-पीपीओ) को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया गया, जिससे डिजी लॉकर में एक स्थायी पीपीओ रिकॉर्ड बनाया गया। डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशन भोगियों को डोरस्टेप सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा में छूट दी गई है।

4.66 भारत सरकार ने 4.7 करोड़ के कुल लाभार्थी कवरेज के साथ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडी पीएस) को लागू कर रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयोगानुसार भुगतान करें (पे-एज-यू-गो) परिभाषित लाभ योजना के साथ प्राथमिक पेंशन प्रणाली के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को जनवरी 2004 में पेश किया गया था। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस सरकार के सह-योगदान के साथ परिभाषित अंशदान योजना है। पेंशन कॉर्पस का मूल्य मार्क-टू-मार्केट है, और तदनुसार, वापसी की दर बाजार निर्धारित होती है। एनपीएस को वर्ष 2009 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (स्वैच्छिक आधार पर) सहित 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए विस्तारित किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के सभी वर्गों के लिए बचत का अवसर उपलब्ध है। पीएफआरडीए ने पीएसयू सहित कॉर्पोरेट संस्थाओं के कर्मचारियों को एनपीएस, प्रदान करने के लिए वर्ष 2011 में 'एनपीएस-कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल' लॉन्च किया।

4.67 सरकार ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के व्यापक उद्देश्य के एक हिस्से के रूप में जून 2015 में एपीवाई की शुरुआत की। यह योजना 18-40 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, जिसमें वंचितों, असंगठित और निम्न-आय वाले व्यक्तियों पर जोर दिया जाता है। एनपीएस और हाल ही में, एपीवाई की शुरुआत के बाद से, भारत के पेंशन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। एनपीएस और एपीवाई के तहत ग्राहकों की कुल संख्या ने नवंबर 2022 में 25.1 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, इसी अवधि के दौरान एयूएम में 22.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। समग्र योगदान में नवंबर 2022 में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें अधिकतम वृद्धि कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा अपनाए गए ऑल-सिटिजन मॉडल द्वारा दर्ज की गई।

**तालिका 17: भारत के पेंशन क्षेत्र का प्रदर्शन**

	ग्राहक संख्या		साल दर साल	योगदान ( करोड़ )		साल दर साल	एयूएम ( करोड़ )		साल दर साल
	Nov-21	Nov-22	प्रतिशत	Nov-21	Nov-22	प्रतिशत	Nov-21	Nov-22	प्रतिशत
सीजी+एसजी									
कॉर्पोरेट+सभी नागरिक	77	83	8	3,93,690	4,89,855	24	5,55,932	6,67,255	20
एनपीएस लाइट	32	42	31	8,41,80	1,19,817	42	1,07,554	1,46,705	36
एपीवाई	325	429	32	16,877	22,437	33	19,352	24,829	28

स्रोत: पीएफआरडीए

सीजी का मतलब केंद्र सरकार और एसजी का मतलब राज्य सरकार है

4.68 वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2021 की पांच वर्ष की अवधि के लिए एनपीएस ग्राहकों (सभी नागरिक मॉडल) की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं पर पीएफआरडीए16 द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 24 प्रतिशत महिला ग्राहक थीं, शेष 76 प्रतिशत पुरुष ग्राहक थे। यह एपीवाई के मामले में बेहतर लिंग संतुलन के विपरीत है। एपीवाई के तहत महिला ग्राहक योजना के शुरुआती वर्षों में लगभग 38 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 तक लगभग 44 प्रतिशत हो गई हैं। विभिन्न राज्यों में, महाराष्ट्र से नामांकन सबसे अधिक था, जो 17 प्रतिशत था। एपीवाई योजना में ग्राहकों की आयु प्रोफाइल कम उम्र में बढ़ते नामांकन का सुझाव देती है। अगस्त 2022 तक, 44.8 प्रतिशत ग्राहक 18 से 25 वर्ष के बीच थे, जबकि मार्च 2016 में यह 29.3 प्रतिशत था। इसके अलावा, अधिक लोग अब प्रति माह ₹ 1000 की पेंशन राशि का विकल्प चुन रहे हैं। मार्च 2022 तक, लगभग 76 प्रतिशत ग्राहकों ने [ 1000 प्रति माह पेंशन राशि का विकल्प चुना है, जबकि मार्च 2016 में यह संख्या 38 प्रतिशत थी। हालांकि, ₹ 5000 प्रति माह पेंशन का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों की संख्या मार्च 2016 में 47 प्रतिशत से घटकर मार्च 2022 तक 15 प्रतिशत हो गई है। कुल जनसंख्या के भाग के रूप में एनपीएस और एपीवाई के तहत पेंशन में जनसंख्या का कवरेज वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2022 तक के छह वर्षों के दौरान 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में आस्तियां 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गई है, यह दर्शाता है कि पेंशन क्षेत्र अर्थव्यवस्था और जनसंख्या की नाममात्र वृद्धि की तुलना में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है।

4.69 पीएफआरडीए ने ग्राहकों के लिए एनपीएस और एपीवाई की पहुँच को आसान बनाने के लिए निपटारे को संसाधित करने की समय-सीमा को घटाकर टी+2 करना जैसे कई उपाय किए हैं। सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों ने इलेक्ट्रॉनिक-पेंशन सेवानिवृत्ति खाता संख्या (ई-पीआरएन), इलेक्ट्रॉनिक खाता विवरण और आधार और

डिजिलॉकर-आधारित खाता खोलने जैसी ग्राहक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिलॉकर के साथ अपनी प्रणालियों को एकीकृत किया है। सरकारी क्षेत्र के ग्राहक सीआरए लॉगइन में सीधे अनुरोध सबमिट करके अपने निवेश विकल्पों को ऑनलाइन बदल सकते हैं। एनपीएस ग्राहकों के लाभ के लिए यूपीआई हैंडल के माध्यम से योगदान स्वीकार किया जा सकता है, जिससे उन्हें सीआरए द्वारा प्रदान किए गए वर्चुअल अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने पीआरएएन में धन भेजने की अनुमति मिलती है।

4.70 भारत के पेंशन क्षेत्र में विकास की जबरदस्त विषय-क्षेत्र है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में और वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि अर्थव्यवस्था एक उच्च-मध्यम-आय वाले देश में परिवर्तित हो रही है। भारत की जनसांख्यिकीय संरचना, युवा लोगों के अधिक महत्वपूर्ण अनुपात के साथ, संचय के एक चरण का समर्थन करती है। हालांकि, न केवल उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं बल्कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के तत्वावधान में पीएफआरडीए, ने वित्तीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि उपभोक्ता सही निर्णय ले सकें और शामिल किए गए जोखिमों और विभिन्न व्यापार-नापसंदों के प्रति सचेत रहते हुए औपचारिक वित्तीय क्षेत्र का लाभ उठा सकें। इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पेंशन शिक्षा, व्यापार निकायों के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रम, बैंक जैसे मध्यस्थ और टाउन हॉल कार्यक्रम शामिल हैं।

4.71 भारत का पेंशन क्षेत्र वेतनभोगी कर्मचारियों और आम व्यक्ति के लिए वृद्धावस्था आय-सुरक्षा का एक लचीला तरीका प्रदान करता है। हाल के पांच वर्षों में, वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2022 तक, ग्राहकों की संख्या तीन गुना से अधिक हो गई है, जिसमें एपीवाई, और एयूएम चार गुना से अधिक, एनपीएस में हुआ है। एनपीएस में भविष्य में विस्तार वेतनभोगी और स्वरोजगार दोनों, निजी क्षेत्र से निकलने की संभावना है। पेंशन योजना में शामिल होने के लिए, युवा वयस्कों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ नियामक और सरकार की ओर से प्रोत्साहन के साथ-साथ ग्राहकों और बिचौलियों दोनों के लिए बढ़ी हुई पेंशन साक्षरता की दिशा में कदम, पेंशनयुक्त समाज की दिशा में आंदोलन को गति प्रदान करेंगे।

## दृष्टिकोण

4.72 घरेलू वित्तीय प्रणाली का लचीलापन बैंकों की स्वस्थ बैलेंस शीट, एनबीएफसी के मजबूत पूंजीगत स्तर और घरेलू म्यूचुअलफंड के एयूएम में मजबूत वृद्धि में परिलक्षित होता है। आस्ति की गुणवत्ता में सुधार, लाभप्रदता में वापसी और लचीला पूंजी और नकदी बफर्स से बैंक ऋण की प्रचंड मांग और निवेश चक्र में पुनरुद्धार के शुरुआती संकेत लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा, आईबीसी तंत्रफर्मों के लिए समयबद्ध प्रस्तावों के साथ आसान निकास की सुविधा देकर भारत में व्यापार करने में आसानी का समर्थन करना जारी रखता है। ये ताकतें चाहे बाहरी स्पिलओवर से, वैश्विक वित्तीय स्थितियों को सख्त करके और वित्तीय बाजारों में उच्च अस्थिरता से वित्तीय प्रणाली की मदद कर रही हैं।

4.73 भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक है और 2032 तक शीर्ष छह बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने की उम्मीद है। बीमा कंपनियों के लिए एफडीआई सीमा में वृद्धि के साथ भारत के बीमा बाजार का डिजिटलीकरण होने की संभावना है। दीर्घावधि पूंजी, एक वैश्विक प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के बढ़ते प्रवाह की सुविधा प्रदान करना, जो भारत के बीमा क्षेत्र के विकास का समर्थन करेगा। साथ ही, जब हम एक उच्च मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, भारत के पेंशन क्षेत्र में विकास की जबरदस्त गुंजाइश है। ग्राहकों और बिचौलियों की पेंशन साक्षरता बढ़ाने की दिशा में सरकार की पहल, और युवा वयस्कों को पेंशन योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नियामक और सरकार की ओर से समाज के अधिक व्यापक वर्ग के लिए पेंशन उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।